RNI No. MPHIN/2015/64451 डाक पंजीयन क्र. MP/IDC/1525/2019-2021 IPT डाक द्वारा प्रेषण प्रति शुक्रवार indianplasttimes@gmail.com

www.Indianplasttimes.in

इंडियन प्लास्ट टाइम्स

■ INDORE ■ 29 SEPTEMBER TO 05 OCTOBER 2021 ■ प्रति बुधवार ■ वर्ष 07 ■ अंक 5 ■ पृष्ठ 8 ■ कीमत 5 रु.

Inside News

जीएसटी कर स्लैब की समीक्षा और कर चोरी स्रोतों की पहचान करने को दो मंत्री समूह गठित Page 3

चीन में बिजली गुल, दुनिया भर की फैक्ट्रियों में हड़कंप .. Page 4

अमेरिका में क्रिसमस ट्री की लागत बढी चीन से आने वाला सामान पोर्ट पर अटका Page 7

editoria!

बेहतर होती आर्थिकी

कोरोना महामारी के असर में कमी के साथ अर्थव्यवस्था में भी सुधार के ठोस लक्षण दिखने लगे हैं. अगस्त में फैक्ट्री गतिविधियों में बढ़त है यानी बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन में तेजी आ रही है. महामारी का सबसे गंभीर असर सेवा क्षेत्र पर पड़ा है, पर अब उसमें भी वृद्धि हो रही है, जो चार माह में पहली बार है. निर्यात बीते साल अगस्त की तुलना में इस अगस्त में करीब 46 फीसदी अधिक रहा है. भारत उन कुछ देशों में है, जिनका निर्यात बढ़ रहा है. अर्थव्यवस्था के संदर्भ में सबसे अधिक चिंता मांग की कमी रही है. बाजार में मांग बढ़ती है, तभी औद्योगिक एवं कारोबारी गतिविधियां तेज होती हैं. ऐसा होने पर रोजगार और आमदनी में भी बढ़ोतरी होती है तथा अर्थव्यवस्था अग्रसर होती है. बीते कुछ महीने से उपभोक्ता संकेतक भी सकारात्मक रुझान दिखा रहे हैं. पिछले साल महामारी की पहली लहर के दौरान संक्रमण रोकने के इरादे से लगाये गये लॉकडाउन की वजह से कई महीनों तक आर्थिक गतिविधियां ठप रही थीं. लेकिन पाबंदियों के हटने के साथ अच्छे नतीजे आने शुरू ही हुए थे कि देश को भयावह दूसरी लहर की आक्रामकता का सामना करना पड़ा. तब महामारी को रोकने के लिए एक बार फिर विभिन्न प्रकार की पाबंदियों को अपनाना पड़ा, किंतु पिछले अनुभवों से सीख लेते हुए उन्हें ऐसे लागू किया गया कि नकारात्मक असर कम-से-कम हो. अब जब अर्थव्यवस्था न केवल पटरी पर है, बल्कि आगे भी बढ़ रही है. बैंक कर्ज में वृद्धि भी इंगित कर रही है कि लोग अब खर्च करने की स्थिति में भी हैं और उनकी ऐसी मंशा भी है. उत्सवों के दिन आ रहे हैं. ये सभी संकेतक बता रहे हैं कि आगामी दिनों में बाजार में हलचल और बढ़ेगी. इस उम्मीद काएक बड़ा आधार अप्रैल और जून के बीच रोजगार में 29 प्रतिशत की बड़ी बढ़त भी है. कोरोना संकट ने बेरोजगारी को चिंताजनक स्तर पर ला दिया था. ऐसे में इस वृद्धि से चालू वित्त वर्ष की शेष तिमाहियों में भी वृद्धि दर के संतोषजनक होने का भरोसा मिलता है. उल्लेखनीय है कि यह बढ़त लगभग सभी क्षेत्रों में दर्ज की गयी है. विशेषज्ञों की मानें, तो इस बढ़ोतरी की दो मुख्य वजहें हैं. पहली वजह पिछले डेढ़ साल में सरकार की ओर बड़े पैमाने पर आर्थिक राहत तथा कल्याणकारी योजनाएं देना है. सूक्ष्म, छोटे व मझोले उद्यमों के लिए विशेष पहले हुई हैं. कर्जों की चुकौती में राहत तथा ऋण उपलब्धता से भी उद्योगों एवं कारोबारों को बड़ी मदद मिली है. गरीबों के लिए ग्रामीण रोजगार तथा मुफ्त अनाज देने की योजनाओं से करोड़ों लोगों को फौरी राहत मिली है. दूसरी वजह है, दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान, जिसके तहत आधी से अधिक आबादी को कम-से-कम एक खुराक मिल चुकी है. ऐसे में उम्मीद है कि आर्थिक वृद्धि की यह गति आगे और तेज होगी.

पेट्रोल-डीजल कीमतों में अभी और भड़केगी आग

महंगाई की आग में उबल रहा कच्चा तेल, सस्ता होने के लिए अब जीएसटी से ही उम्मीद

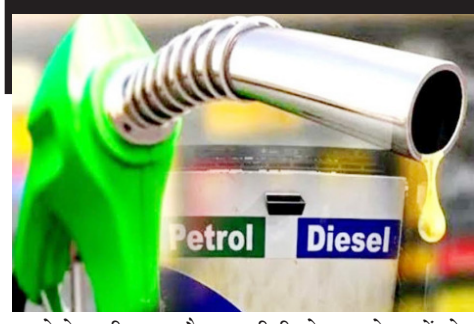

पेट्रोल-डीजल और एलपीजी के उपभोक्ताओं के लिए एक बुरी खबर है। कच्चे तेल की कीमतों में लगातार उछाल से इनके दाम कम होने की उम्मीदों को झटका लगना तय है। अब पेट्रोल-डीजल तभी सस्ता हो सकता जब केंद्र और राज्य सरकारें अपने टैक्स में कटौती करें या फिर इसे जएसटी के दायरे में लाएं।

कच्चे तेल का भाव 90 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंचने का अनुमान

गोल्डमैन सैक्स के इस साल के अंत तक कच्चे तेल का भाव 90 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंचने के अनुमान के साथ, ऊर्जा आयात पर निर्भर अर्थव्यवस्थाएं अब मुश्किल में हैं। भारत अपने तेल का 85% और अपनी गैस आवश्यकताओं का 53% आयात करता है।

क्या है भारत की तैयारी

भारत घरेलू तेल और गैस उत्पादन बढ़ाने के लिए निजी निवेश पर विचार कर रहा है, जो पिछले कुछ वर्षों से स्थिर है। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में 2022 तक भारत की तेल निर्भरता को 10% से 67% (वित्त वर्ष 2015 में आयात निर्भरता के आधार पर 77%) कम करने का लक्ष्य रखा था। भारत के गैस उत्पादन में वृद्धि हुई है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की ओर से जारी मासिक उत्पादन रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त में गैस उत्पादन में 20.23 फीसदी की बढ़ोतरी हुई।

मूल्य वृद्धि का भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा

कच्चे तेल की कीमतों में हालिया उछाल ने भारतीय रिजर्व बैंक और नीति आयोग दोनों को केंद्र और राज्यों को व्यवसायों पर इनपुट लागत दबावों को नियंत्रित करने की आवश्यकता पर ध्यान देने के लिए प्रेरित किया। रेट में एक और उछाल टैक्स में कटौती का दबाव डाल सकता है। इससे राजस्व और खर्च प्रभावित हो सकते हैं। एक साल पहले की अवधि से जून तिमाही में सरकारी खर्च में पहले ही कमी देखी गई थी। आरबीआई ने वित्त वर्ष 22 में अर्थव्यवस्था के 9.5% बढ़ने का अनुमान लगाया है, जिसमें जून तिमाही में 21.4% विस्तार और सितंबर तिमाही में 7.3%, दिसंबर तिमाही में 6.3% और मार्च तिमाही में 6.1% शामिल है।

क्या उपभोक्ताओं को चिंतित होना चाहिए?

ओमान, दुबई और ब्रेंट के औसत का प्रतिनिधित्व करने वाले कच्चे तेल की इंडियन बास्केट की कीमत पिछले साल अप्रैल में कोरोनोवायरस महामारी की पहली लहर के दौरान गिरकर 19.90 डॉलर हो गई थी। इसने केंद्र सरकार को पेट्रोल और डीजल पर टैक्स को तेजी से बढ़ाने का मौका दिया, जिससे उत्पाद शुल्क वित्त वर्ष 2021 में सरकारी खजाने में प्रमुख योगदानकर्ताओं में से एक बन गया। जब तक टैक्स में कटौती नहीं की जाती है तेल की कीमतों में कोई भी बढ़ोतरी उपभोक्ताओं को और परेशान करेगी। बता दें 27 सितंबर को कच्चे तेल की कीमत 76.89 डॉलर प्रति बैरल थी।

कच्चे तेल की कीमतों में तेजी की वजह

पूरी दुनिया में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट में नरमी आने के बाद लोगों की गतिविधियां तेज हुई हैं और ईंधन की मांग तेजी से बढ़ रही है। अभी हाल में अमेरिका में आए तूफान आईडा की तबाही से भी तेल सप्लाई पर गंभीर असर देखा जा रहा है। यह ऐसे समय में आया है, जब वैश्विक स्तर पर तेल की मांग बढ़ रही है, लेकिन उद्योग को अगले साल तेल की कीमतों में नरमी दिख रही है। एसएंडपी ग्लोबल प्लैट्स ने कहा, 'कीमतें 2022 में कम होकर 65-70 डॉलर प्रति बैरल (औसतन) हो सकती हैं।'

कच्चे तेल के आयात पर खर्च

भारत ने वित्त वर्ष 2021 में कच्चे तेल के आयात पर 62.71 अरब डॉलर, वित्त वर्ष 2020 में 101.4 अरब डॉलर और वित्त वर्ष 2019 में 111.9 अरब डॉलर खर्च किए। यह 249.36 मिलियन टन प्रति वर्ष (एमटीपीए) से अधिक की स्थापित क्षमता के साथ एशिया में एक प्रमुख रिफाइनिंग हब है। भारत 'रिस्पांसिबल प्राइस' पर वैश्विक सहमति बनाने की बात कर रहा है, क्योंकि उसकी 2025 तक अपनी शोधन क्षमता को 400 मिलियन टन प्रति वर्ष तक बढ़ाने की योजना है। भारत में डीजल और पेट्रोल की कीमतें पहले ही 100 रुपये के स्तर को पार कर चुकी हैं और रिकॉर्ड उच्च स्तर पर हैं। घरेलू डीजल की मांग दिवाली तक प्री-कोविड-19 के स्तर तक पहुंचने की उम्मीद है।

कच्चा तेल 80 डॉलर पार, डीजल-पेट्रोल स्थिर

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के तीन वर्ष के उच्चतम स्तर 80 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंचने के बीच बुधवार को घरेलू स्तर पर डीजल और पेट्रोल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया। मंगलवार को डीजल लगातार तीसरे दिन 25 पैसे प्रति लीटर और पेट्रोल 22 दिनों के बाद 20 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया था। डीजल की कीमत पिछले पांच दिनों में से चार दिन में 95 पैसे प्रति लीटर चढ़ गया है। यूरोप में ऊर्जा संकट के कारण कल कच्चे तेल में लगातार सातवें दिन तेजी दर्ज की गई। इससे पहले अमरीका के तेल भंडार में कमी आने की वजह से कच्चे तेल में तेजी आयी थी। कल अमरीकी बाजार में कारोबार बंद होने पर ब्रेट क्रूड 80 डॉलर प्रति बैरल के पार 80.69 डॉलर प्रति पर पहुंच गया। इस दौरान अमेरिकी क्रूड भी 1.49 डॉलर की बढ़त के साथ 75 डॉलर के पार 75243 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया। विश्लेषकों का कहना है कि इस वर्ष के अंत तक कच्चा तेल 90 डॉलर प्रति बैरल के पार जा सकता है। कोरोना वायरस के संक्रमण के वैश्विक स्तर पर लगभग काबू में आने के बाद तेल की मांग आने लगी है, जिससे कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है।

News यू केन USE

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने सत्यापन शुल्क घटाकर 3 रुपये किया: सीईओ

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने ग्राहकों के लिये आधार सत्यापन को लेकर राशि 20 रुपये से कम कर 3 रुपये कर दी है। इस पहल का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि इकाइयां विभिन्न सेवाओं और लाभों के जरिये लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिये उसकी ढांचागत सुविधाओं का लाभ उठायें। एनपीसीआई-आईएएमएआई द्वारा आयोजित वैश्विक फिनटेक फेस्ट को संबोधित करते हुए यूआईडीएआई के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) सौरभ गर्ग ने कहा कि वित्तीय प्रौद्योगिकी क्षेत्र में आधार का लाभ उठाने की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा, ''हमने प्रति सत्यापन की दर 20 रुपये से घटाकर 3 रुपये कर दी है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विभिन्न एजेंसियां और संस्थान सरकार द्वारा तैयार डिजिटल बुनियादी ढांचे का बेहतर उपयोग कर सकें। मान-सम्मान के साथ लोगों के जीवन को सुगम बनाने के लिये इन बुनियादी ढांचों का उपयोग जरूरी है।'' अब तक 99 करोड़ ई-केवाईसी (अपने ग्राहक को जानें) के लिये आधार प्रणाली का उपयोग किया गया है।

दिवाली के मौके पर यूके रॉयल मिंट द्वारा देवी लक्ष्मी की तस्वीर वाली सोने की छड़ की होगी बिक्री

लंदन। एजेंसी

दीवाली के मौके पर अब विदेशों में भी धन की देवी लक्ष्मी वाले सोने के सिक्के और छड़ों की बिक्री की जा रही है। ब्रिटेन की रॉयल मिंट ने मंगलवार को पहली बार देवी लक्ष्मी की छवि वाली स्वर्ण 'बार रेंज' की बिक्री शुरू की है। सोने की यह 'बार' 20 ग्राम में है जिसमें धन की देवी लक्ष्मी की छवि अंकित है। रॉयल मिंट के डिजाइनर एम्मा नोबल ने इसका डिजाइन तैयार किया है। इस स्वर्ण बिस्कुट की खुदरा कीमत 1,080 पाउंड है, जिसे रॉयल मिंट द्वारा विविधता और समावेश के प्रति उसकी सतत प्रतिबद्धता और देश में विविध सांस्कृतिक समारोहों के विस्तार के रूप में वर्णित किया है। रॉयल मिंट में बहुमूल्य धातु खंड के 'डिवीजनल डायरेक्टर' एंड्रयू डिकी ने कहा, ''दिवाली त्योहार के दौरान सोना एक पारंपरिक और शुभ उपहार होने के साथ, हम एक ऐसा उत्पाद विकसित करना चाहते थे, जिसमें सुंदरता और परंपरा दोनों शामिल हों और इसमें आधुनिकता का समावेश भी हो।''

2005 से 'अपडेट' नहीं हुए आयातक-निर्यातक कोड छह अक्टूबर से निष्क्रिय किए जाएंगे

नयी दिल्ली। एजेंसी

वाणिज्य मंत्रालय ने जनवरी, 2005 से अद्यतन (अपडेट) नहीं हुए सभी आयातक-निर्यातक कोड (आईईसी) को इस वर्ष छह अक्टूबर से निष्क्रिय करने का निर्णय लिया है। इस कदम से देश में व्यापारियों की वास्तविक संख्या का पता लगाने में मदद मिलेगी। आयातक-निर्यातक कोड (आईईसी) एक प्रमुख व्यावसायिक पहचान संख्या है, जो निर्यात या आयात के लिए अनिवार्य है। कोई भी व्यक्ति विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) द्वारा दिए गए आईईसी नंबर के बिना आयात या निर्यात नहीं कर सकता है। डीजीएफटी के व्यापार नोटिस के अनुसार, ''विदेश व्यापार महानिदेशालय ने इस वर्ष आठ अगस्त को सभी आईईसी धारकों से अपना विवरण हर साल अप्रैल-जून अवधि के दौरान इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपडेट करने के लिए कहा था। जो भी आईईसी कोड एक जनवरी, 2005 के बाद से अपडेट नहीं पाए जायेंगे, उन्हें छह अक्टूबर, 2021 से निष्क्रिय कर दिया जाएगा।'' उसने कहा कि आईईसी धारकों को पांच अक्टूबर तक अपने आईईसी कोड को अद्यतन करने का एक अंतिम मौका दिया जा रहा है। वही मंजूरी के लिए डीजीएफटी आरए (क्षेत्रीय प्राधिकरण) के जमा कराए गए ऑनलाइन अद्यतन आवेदन यदि लंबित हैं, तो उन्हें आईईसी कोड को निष्क्रिय करने की सूची से बाहर रखा जाएगा।

कच्चा तेल हुआ और महंगा, भारत में हुई बुधवार के लिए पेट्रोल-डीजल की कीमतों की घोषणा

नई दिल्ली। एजेंसी

कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों ने भारत सहित दुनिया के लगभग सभी देशों को मुश्किल में डाल दिया है। भारत में पहले से ही पेट्रोल की कीमतें 100 रुपये के पार पहुंच गई हैं। वहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमत 80 डॉलर प्रति बैरल के पार चली जाने से एक बार फिर तेल की कीमतों में आग लगने का अंदेशा व्यक्त किया जात रहा है। बता दें कि कच्चा तेल अक्टूबर 2018 के बाद से अपने उच्चतम स्तर पर है।लेकिन कच्चे तेल में उफान के बावजूद बुधवार को सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया। इससे पहले पेट्रोल की कीमत में मंगलवार को 20 पैसे की बढ़ोतरी की गई थी, डीजल की कीमत में 5 दिन में 95 पैसे की बढ़ोतरी हुई। दिल्ली में बुधवार को इंडियन ऑयल के पंप पर पेट्रोल प्रति लीटर 101.39 रुपये और डीजल 89.57 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है।

अन्य शहरों में क्या हैं तेल के दाम

अन्य शहरों की बात करें तो मुंबई में पेट्रोल 107.47 और डीजल 97.21 रुपये, चेन्नई में पेट्रोल 99.15 और डीजल 94.17, कोलकाता में पेट्रोल 101.87 और डीजल 92.67, भोपाल में पेट्रोल 109.85 और 98.45 डीजल, रांची में पेट्रोल 96.37 और डीजल 94.58, बेंगलुरु में पेट्रोल 104.92 और डीजल 95.06, पटना में पेट्रोल 104.04 और डीजल 95.70, चंडीगढ़ में पेट्रोल 97.61 और डीजल 89.31, लखनऊ में पेट्रोल 98.51 और डीजल 89.98, नोएडा में पेट्रोल 98.73 और डीजल 90.17 रुपये पर मिल रहा है।

कच्चा तेल 80 डॉलर के पार

कच्चे तेल की कीमतों में मंगलवार को लगातार सातवें दिन तेजी आई। मंगलवार को ब्रेंट क्रूड 80 डॉलर प्रति बैरल के भी पार चला गया। ब्रेंट क्रूड 80.69 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया जो अक्टूबर 2018 के बाद इसका उच्चतम स्तर है। डब्ल्यूटीआई क्रूड भी 01.49 डॉलर बढ़ कर 75.43 डॉलर प्रति बैरल पर बंद हुआ।

वैश्विक कारणों से बाजार की कमजोर शुरुआत, निफ्टी 17,700 के नीचे आया

मुंबई। आईपीटी नेटवर्क

वैश्विक कारणों से बुधवार को बाजार की कमजोर शुरुआत हुई है। एक्सपायरी के एक दिन पहले बाजार गिरावट के साथ खुले। सेंसेक्स 59,296 पर और निफ्टी 17,657 पर खुला। फिलहाल सेंसेक्स लगभग 350 अंक गिरकर 59290 के आस-पास कारोबार कर रहा है। वहीं, निफ्टी लगभग 100 अंक गिरकर 17,650 के करीब कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स के 30 शेयर्स में से 22 शेयर्स कमजोरी के साथ और 8 शेयर्स बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं। जिसमें एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक और बजाज ऑटो के शेयर 1इ से ज्यादा गिरकर कर कारोबार कर रहे थे। वहीं पावर ग्रिड के शेयर 1इ की तेजी के साथ ट्रेड कर रहे थे। बाजार में बैंकिंग और ऑटो शेयर्स पर दबाव देखने को मिल रहा था। एनएसई पर निफ्टी बैंक करीब डेढ़ पर्सेंट और ऑटो इंडेक्स 1इ ज्यादा की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। वहीं फार्मा इंडेक्स से बाजार को सपोर्ट मिल रहा है। फार्मा इंडेक्स करीब आधा पर्सेंट ऊपर कारोबार कर रहा है।

US मार्केट में तेज गिरावट, एशिया कमजोर

ग्लोबल मार्केट से संकेत कमजोर नजर आ रहे है. एशिया में निक्की 2 परसेंट से ज्यादा टूटा है। एसजीएक्स निफ्टी पर भी दबाव देखने को मिला। उधर अमेरिका में बॉन्ड यील्ड में मजबूती से टेक शेयरों में भारी गिरावट आई है।नेस्डेक बीते दिन में पौने 3 परसेंट फिसला और डॉओ भी 570 अंक नीचे बंद हुआ। हालांकि बुधवार को डॉओ फ्यूचर में 150 प्वाइंट की मजबूती देखने को मिल।

दुबई एक्सपो में भारत अपनी उपलब्धियों और सांस्कृतिक विविधता का प्रदर्शन करेगा: अधिकारी

दुबई। एजेंसी

भारत एक अक्टूबर से शुरू हो रहे दुबई एक्सपो 2020 में अपनी कला, संस्कृति और व्यंजनों के साथ ही अपनी प्रमुख उपलब्धियों का प्रदर्शन करेगा। भारतीय दूतावास ने यह जानकारी दी। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में भारत के राजदूत पवन कपूर ने कहा, ''यह बहुत स्पष्ट है कि हमारी जनसंख्या के अनुपात के आधार पर, यहां हमारे जिस तरह के संपर्क हैं, हम दुबई एक्सपो में सबसे बड़े भागीदार होंगे।'' यह आयोजन 183 दिन तक चलेगा और 31 मार्च 2022 को खत्म होगा। इस दौरान भारतीय मंडप में दुनिया को भारत की सांस्कृतिक विविधता, प्राचीन धरोहर, व्यावसायिक उपलब्धियों और अत्याधुनिक तकनीकों से परिचित कराया जाएगा। भारतीय मंडप दुबई एक्सपो 2020 में सबसे बड़े मंडपों में से एक है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया, ''भारतीय मंडप में दुनिया देश की सांस्कृतिक विविधता, प्राचीन धरोहर, व्यावसायिक उपलब्धियों और अत्याधुनिक तकनीकों के साथ अग्रणी अवसरों का अनुभव करेगी। इसमें एक आधुनिक भारत के साथ ही भारतीय कला, संस्कृति और व्यंजनों को प्रदर्शित किया जाएगा। यह कार्यक्रम 183 दिन तक चलेगा।'' केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग तथा कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल एक अक्टूबर को भारतीय दीर्घा का उद्घाटन करेंगे।

वाणिज्य सप्ताह एक बड़ी सफलता जिसे संस्थागत बनाये जाने की आवश्यकता है: फियो अध्यक्ष डॉ. ए शक्तिवेल

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने वाणिज्य सप्ताह के समापन को संबोधित करते हुए कहा कि सप्ताह भर चलने वाले समारोहों एवं व्यवसाय ने देश के कोने कोने में निर्यातकों के बीच नए उत्साह का संचार कर दिया है। निर्यातकों की बैठकों ने जमीनी स्तर पर जागरूकता पैदा की है और अंतरालों की पहचान की है जिसे भरे जाने की आवश्यकता है। श्री गोयल ने यह भी कहा कि ' निर्यात हब के रूप में जिला' के तहत, 739 जिलों की संभावित निर्यात उत्पादों के साथ पहचान की गई है। वाणिज्य सप्ताह के दौरान प्रदर्शित किए जाने से ब्रांड इंडिया को बढ़ावा मिला है और इससे उद्यमियों, विशेष रूप से स्टार्ट अप्स को प्रोत्साहन प्राप्त होगा। उन्होंने सुझाव दिया कि हम वाणिज्य सप्ताह को संस्थागत कर सकते हैं और निर्यात लक्ष्य को प्रोजेक्ट करने तथा इसका मूल्यांकन करने के लिए हम क्रमशः अप्रैल और अक्टूबर में इसका आयोजन कर सकते हैं। श्री गोयल ने उद्योग से दुबई 2020 में भाग लेने का आग्रह किया क्योंकि दुबई शोकेस करने के लिए एक शानदार जगह है। इस सहभागिता से देश द्वारा लगाये गए शानदार इंडिया पैवेलियन की एक झलक भी मिलेगी। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने कंटेनरों की मांग का पूर्वानुमान लगाने के द्वारा कंटेनरों की कमी की समस्या को दूर करने के लिए फियो द्वारा विकसित इज ऑफ लॉजिस्टिक्स पोर्टल का उद्घाटन किया। फियो अध्यक्ष डॉ. ए शक्तिवेल ने कहा कि यह पोर्टल निर्यातकों तथा सेवा प्रदाताओं, दोनों के लिए लाभदायक स्थिति है। डॉ. शक्तिवेल ने कहा कि यह पोर्टल सभी हितधारकों को मूल्य प्रस्ताव की पेशकश करता है। निर्यातक सीधे सेवा प्रदाताओं को उनका सर्वश्रेष्ठ उद्धरण (कोट) उपलब्ध कराने के लिए अपनी कंटेनर आवश्यकताओं का विवरण पोस्ट कर सकते हैं जिससे उन्हें चैट करने, परस्पर बातचीत करने तथा व्यवसाय को अंतिम रूप देने में मदद मिलती है। उन्होंने उम्मीद जताई कि मांग की व्यापक दृश्यता के साथ निर्यातक बेहतर कीमत की खोज कर सकते हैं और इस पोर्टल के जरिये उनकी कंटेनर पूर्ति की संभावना में सुधार होगा। दूसरी तरफ, मांगों के बारे में अग्रिम रूप से जानकारी मिलने से लॉजिस्टिक्स सेवा प्रदाता -एलएसपी इक्विपमेंट को लेकर योजना बनाने तथा कंटेनर रिपोजिशनिंग की बेहतर स्थिति में होंगे और देश भर के निर्यातकों की मांगों तक पहुंच प्राप्त करने के लिए साथ ही उन्हें व्यापक व्यापार पहुंच भी प्रदान करेंगे। फियो अध्यक्ष ने एमईआईएस, एसईआईएस, रोडटेप, आरओएससीटीएल तथा अन्य लंबित दावों को जारी करने, जिससे उनकी तरलता बाधाएं दूर होंगी, के लिए भी मंत्री महोदय को धन्यवाद दिया। राष्ट्रीय एकल विंडो प्रणाली का उल्लेख करते हुए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने कहा कि यह पोर्टल व्यापक सुविधा प्रदान के द्वारा एक ही क्लिक पर सभी समाधानों तक पहुंच सुलभ कराने में निर्यातकों की मदद करेगा। इसका परिणाम निर्बाधित प्रक्रिया के रूप में सामने आएगा और इससे पारदर्शिता तथा जवाबदेही में बढोतरी होगी। उन्होंने कहा कि कई क्षेत्रों में भारतीय विनिर्माता बहुत प्रतिस्पर्धी हैं जिससे निर्यात के लिए मजबूत संभावना बनती है। हम वृद्धिशील निर्यातों की तरफ नहीं बल्कि निर्यातों को रूपांतरित करने की ओर देख रहे हैं। इसी के साथ साथ, जिन उत्पादों में देश में कच्चे मालों की अनुपलब्धता के कारण हम प्रतिस्पर्धी नहीं हैं, हमें उन्हें आयात करना पड़ता है। कुछ मामलों में निर्यात और विनिर्माण आयात पर निर्भर होते हैं। इसलिए, आत्म निर्भर होने का अर्थ यह नहीं लगाया जाना चाहिए कि हम अपने दरवाजे बंद कर रहे हैं। विश्व एक लचीली आपूर्ति श्रृंखला और भरोसेमंद साझीदार की ओर देख रहा है। हमें दुनिया के लिए मेक इन इंडिया बनना है। विदेश व्यापार महानिदेशक श्री अमित यादव ने कहा कि देश में कल एपीडा, एम्पीडा, चाय बोर्ड, कॉफी बोर्ड आदि द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में 15 लाख से अधिक लोगों ने भागीदारी की। वाणिज्य सप्ताह में एक करोड़ से अधिक लोगों ने सहभागिता की जिससे यह अत्यंत सफल बन गया।

जीएसटी कर स्लैब की समीक्षा और कर चोरी स्त्रोतों की पहचान करने को दो मंत्री समूह गठित

नयी दिल्ली। एजेंसी

वित्त मंत्रालय ने जीएसटी प्रणाली के तहत मौजूदा कर स्लैब, जीएसटी से छूट प्राप्त वस्तुओं की समीक्षा करने और कर चोरी के संभावित स्त्रोतों की पहचान करने के लिए राज्यों के वित्त मंत्रियों की दो समितियां गठित की हैं। माल एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली को अमल में लाने के चार साल बाद अब केंद्र और राज्यों ने इसके तहत वर्तमान कर दर स्लैब की समीक्षा कर 'जीएसटी में सरल दर संरचना' की दिशा में बढ़ने पर काम शुरू किया है। इसमें विशेष दरों को लेकर विचार करने के साथ ही स्लैब की कर दरों के विलय पर भी विचार किया जा सकता है। जीएसटी दर को तर्कसंगत बनाने वाला मंत्रियों का समूह (जीओएम) रिफंड भुगतान को कम से कम करने के लिए उल्टा शुल्क ढांचे की समीक्षा करेगा। इसके साथ ही मंत्री समूह जीएसटी प्रणाली के तहत छूट के दायरे में आने वाली सेवाओं और सामानों की आपूर्ति की भी समीक्षा करेगा। इस समीक्षा के पीछे उद्देश्य कर आधार को व्यापक बनाना और इनपुट टैक्स क्रेडिट की श्रृंखला के टूटने की स्थिति को समाप्त करना है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की अध्यक्षता वाली इस समिति में पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा, केरल के वित्त मंत्री के एन बालगोपाल, बिहार के उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद सहित अन्य सदस्य होंगे। सात सदस्यीय यह समिति इस मामले को लेकर दो महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।

जीएसटी की मौजूदा व्यवस्था में आवश्यक वस्तुओं पर या तो कोई कर नहीं लगाया जाता अथवा पांच प्रतिशत की सबसे कम दर पर जीएसटी लगाया जाता है। वहीं कार आदि पर 28 प्रतिशत की सबसे ऊंची दर पर जीएसटी लगाया जाता है। अन्य स्लैब 12 और 18 प्रतिशत की दो मध्यम दर हैं। वहीं विलासिता, अहितकर मानी जाने वाली वस्तुओं पर 28 प्रतिशत की सबसे ऊंची दर पर कर लगाने के साथ ही उसके ऊपर उपकर भी लगाया जाता है।

हाल के वर्षों में जीएसटी की 12 और 18 प्रतिशत की दर को मिलाकर एक दर करने की मांग समय समय पर उठी है। इसके साथ ही जिन वस्तुओं की जीएसटी से छूट मिली है उनमें से कुछ पर छूट समाप्त करने का सुझाव दिया गया ताकि स्लैब को तर्क संगत बनाने से राजस्व पर पड़ने वाले प्रभाव को संतुलित किया जा सके। उल्टी शुल्क संरचना के संबंध में, जीएसटी परिषद पहले ही मोबाइल हैंडसेट, जूते और वस्त्र के मामले में दर की विसंगति को ठीक कर चुकी है। मंत्रिस्तरीय समिति अब उल्टी शुल्क संरचना के अभ्यावेदनों पर ध्यान देगी और ऐसे किसी भी मामले को खत्म करने के लिए उपयुक्त दरों की सिफारिश करेगी जहां अंतिम उत्पाद पर उसके इनपुट पर लगाए गए कर की तुलना में कम जीएसटी लगता है। वहीं जीएसटी प्रणाली सुधारों से जुड़ा मंत्री समूह (जीओएम) कर चोरी के संभावित स्त्रोतों की पहचान करेगा और राजस्व में कमी को रोकने के लिए व्यावसायिक प्रक्रियाओं तथा आईटी प्रणालियों में बदलाव का सुझाव देगा। इसके लिये महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार की अध्यक्षता वाली आठ सदस्यीय समिति में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, तमिलनाडु के वित्त मंत्री पी टी राजन और छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री टी एस सिंह देव सहत अन्य मंत्री शामिल होंगे। समिति कर अधिकारियों के पास उपलब्ध आयकर साधनों एवं इंटरफेस की समीक्षा करेगी तथा उन्हें और ज्यादा कारगर बनाने के तरीके सुझाएगी। बेहतर कर अनुपालन के लिए डेटा विश्लेषण के संभावित इस्तेमाल की पहचान करेगी तथा केंद्रीय एवं राज्य कर अधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय के तरीके सुझाएगी।केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद ने गत 17 सितंबर को हुई बैठक में इन दो मंत्री समूहों का गठन करने का फैसला किया था।

अब आधार वेरिफाई होने पर ही मिलेगा जीएसटी रिफंड, CBIC ने जारी किया यह नया नियम

नई दिल्ली। एजेंसी

अगर आप जीएसटी रिफंड क्लेम करना चाहते

हैं तो आपको अपने आधार का सत्यापन कराना होगा. सरकार ने इस नियम को अनिवार्य कर दिया है। इसका अर्थ हुआ कि जिन लोगों का आधार सत्यापित नहीं होगा, वे जीएसटी का रिफंड नहीं ले पाएंगे। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स (CBIC) ने जीएसटी रूल में संशोधन किया है. जीएसटी के तहत टैक्स चोरी को रोकने के लिए यह संशोधन किया गया है। अब सिर्फ बैंक अकाउंट में ही जीएसटी रिफंड दिया जाएगा। जिस पैन के साथ जीएसटी रजिस्ट्रेशन हुआ रहेगा और उससे जो बैंक खाता जुड़ा रहेगा, उसी पर जीएसटी रिफंड भेजा जाएगा।

कौन भर सकेगा GSTR-1

इससे जुड़ी अधिसूचना में कहा गया है कि 1 जनवरी, 2022 जो बिजनेस सम्मरी रिटर्न फाइल करने में डिफॉल्ट होंगे, हर महीने जीएसटी का पेमेंट नही करेंगे, वे उसके अगले महीने का जीएसटीआर-1 फाइल नहीं कर सकेंगे। यह अधिसूचना जीएसटी काउंसिल की उस बैठक के बाद ली गई जो लखनऊ में 17 सितंबर को चली थी। आधार सत्यापन से जुड़े फैसले पर भी उसी बैठक में विचार किया गया था।

एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के सीनियर पार्टनर रजन मोहन ने PTI को बताया, टैक्स की चोरी रोकने के लिए सरकार ने प्रॉपराइटर, पार्टनर, कर्ता, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर और ऑथराइज्ड सिग्नेटरी के लिए आधार सत्यापन को अनिवार्य कर दिया है। जीएसटी का रिफंड एप्लिकेशन दायर करना हो या रजिस्ट्रेशन के कैंसिलेशन को खत्म करना हो, इसके लिए आधार का सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है।

ईवाई टैक्स पार्टनर के अभिषेक जैन कहते हैं कि सरकारी राजस्व की चोरी रोकने के लिए सरकार ने टैक्सपेयर के लिए आधार सत्यापन अनिवार्य किया है। अब इसी सत्यापन के माध्यम से टैक्सपेयर जीएसटी को क्लेम कर सकेंगे। जैन कहते हैं इस कदम से जीएसटी का फ्रॉड रिफंड रुकेगा क्योंकि जिन टैक्सपेयर्स का आधार वेरिफाई होगा, उन्हें ही जीएसटी रिफंड किया जाएगा।

सरकार ने क्यों उठाया ये कदम

अगर कोई टैक्सपेयर पिछले महीने का जीएसटीआर-3ँ दाखिल नहीं करेगा तो वह जीएसटीआर-1 फाइल नहीं कर सकेगा। इसके बारे में अभिषेक जैन कहते हैं कि यह काफी सोच-समझ कर प्रतिबंध लगाया गया है क्योंकि इससे उन मामलों पर रोक लगेगी जिसमें फर्जी जानकारी देकर जीएसटी फाइल की जाती है। दरअसल टैक्सपेयर जीएसटीआर-1 में सप्लाई इनवॉइस को दिखा देते हैं लेकिन वे जीएसटीआर-3बी रिटर्न को दाखिल नहीं करते हैं जबकि इसी फॉर्म से सरकार को टैक्स का भुगतान होता है. इससे टैक्स बचाने की कोशिश की जाती है। अब जिन लोगों ने पिछले महीने का जीएसटीआर-3बी भरा होगा, वे ही अगले महीने का जीएसटीआर-1 फॉर्म भर सकेंगे। मौजूदा समय में यदि पंजीकृत व्यक्ति बीते दो महीने के जीएसटीआर-3बी फॉर्म में रिटर्न दाखिल नहीं करता है तो उसे जीएसटीआर-1 जमा करने की अनुमति नहीं होती है।

केंद्र ने पूर्वोत्तर में तेल, गैस परियोजनाओं के लिए एक लाख करोड़ रु मंजूर किएः पुरी

गुवाहाटी। एजेंसी

केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में तेल एवं गैस परियोजनाओं के लिए एक लाख करोड़ रुपये की मंजूरी दी है और इन परियोजनाओं के 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है। पुरी ने कहा कि इस क्षेत्र में अन्वेषण का रकबा 2025 तक मौजूदा 30,000 वर्ग किलोमीटर से दोगुना होकर 60,000 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा, जबकि पिछले तीन वर्ष में खुला क्षेत्र लाइसेंस नीति (ओएएलपी) के तहत लगभग 20,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पहले ही आवंटित किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने इस क्षेत्र में बुनियादी ढांचे और आर्थिक विकास की गति को बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की हैं क्योंकि पिछली 'लुक ईस्ट' नीति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'एक्ट ईस्ट' नीति में बदल दिया। पुरी ने क्षेत्र में अन्वेषण और उत्पादन (ईएंडपी) निवेश अवसरों के लिए निवेशकों तथा उद्योगपतियों के साथ एक बैठक के बाद एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र देश के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि उपलब्ध भू-वैज्ञानिक सूचनाओं के अनुसार पूर्वोत्तर क्षेत्र में काफी संभावनाएं हैं और इसलिए क्षेत्र में तेज अन्वेषण के माध्यम से संभावित तेल और गैस के पर्याप्त अवसर मौजूद हैं।

चीन में बिजली गुल, दुनिया भर की फैक्ट्रियों में हड़कंप

मोबाइल से लेकर कार तक की सप्लाई पर होगा असर

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

चीन में बिजली आपूर्ति का संकट गहरा गया है इस वजह से घरों की बिजली काटी जा रही है और फैक्ट्री को उत्पादन कटौती के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। से देश की विशाल अर्थव्यवस्था के धीमा होने और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर दबाव बढ़ने का खतरा है। भारत में कार, टीवी, मोबाइल और अन्य स्मार्ट गैजेट खरीदने वाले ग्राहकों को इस वजह से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

चीन में बिजली के इस संकट की वजह से दुनिया भर में कार और स्मार्टफोन समेत बहुत से इलेक्ट्रौनिक गैजेट के उत्पादन पर असर पड़ सकता है। चीन के औद्योगिक क्षेत्रों में कंपनियों को बिजली की मांग को कम करने के लिए ऊर्जा खपत सीमित करने के लिए कहा गया है। चीन की सरकारी मीडिया की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ घरों में बिजली आपूर्ति में कटौती की गई है, जिससे कुछ लोग लिफ्ट में फंस गए हैं।

बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने में जुटी एजेंसियां

चीन की सभी ताकतवर इकोनामिक प्लैनिंग एजेंसी देश के बिजली संकट को दूर करने में जुट गई हैं। बुधवार को चीन की सभी ताकतवर एजेंसियों ने अपने नागरिकों और कारोबारियों को भरोसा दिया है कि वे बिजली संकट से निपटने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं और बिजली आपूर्ति पर करीबी नजर बनाए हुए हैं, जिससे कि बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

दुनिया भर की फैक्ट्री पर असर

पिछले कुछ सालों में चीन दुनिया भर की फैक्ट्री के लिए कच्चे माल के बड़े आपूर्तिकर्ता के रूप में विकसित हुआ है। दुनिया भर में इलेक्ट्रॉनिक्स, दवा, प्लास्टिक, कार, ऑटोमोबाइल्स और अन्य फैक्ट्रियों के लिए जरूरी सामान की आपूर्ति करने के मामले में चीन दुनिया का अग्रणी देश है। चीन के मौजूदा बिजली संकट के लंबा खिंचने की वजह से दुनिया भर की फैक्ट्रियों में काम प्रभावित हो सकता है। इससे ग्लोबल इकोनामी के संकट में आने और रोजगार एवं अर्थव्यवस्था पर काफी असर पड़ने की आशंका है।

बिजली की सप्लाई क्यों रुकी?

चीन में बिजली संकट मैन्युफैक्चर्स की बढ़ती मांग के बीच कोयला सप्लाई में बाधा के कारण पैदा हुआ है। चीन में कुछ बंदरगाह लंबे समय से बंद थे, ऐसे में पावर प्लांट की मांग के हिसाब से कोयले की सप्लाई नहीं हो पाई। यह आपूर्ति अब भी बाधित है और कोयला मंगाने के लिए बंदरगाहों पर लंबा इंतजार किया जा रहा है। ऐसे में चीन के कई इलाकों में सरकार ने बिजली काटने की घोषणा कर दी है। इन इलाके में मॉल, दुकानें बंद हो गई हैं और फैक्ट्रियों में काम रोकना पड़ गया है।

त्योहारी सीजन पर असर

इन दिनों सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में खिलौने से लेकर कपड़े बनाने वाली कंपनियां तक चीन से कच्चे माल का आयात करती हैं। साल के अंत के त्योहारी सीजन के हिसाब से इस समय दुनिया भर की फैक्ट्रियों में तेजी से काम चल रहा है और चीन के इस संकट की वजह से उनका काम प्रभावित हो सकता है। पिछले कुछ समय में कच्चे माल के भाव बढ़ने और कोरोना संक्रमण जैसे संकट की वजह से भारत समेत दुनिया भर की कंपनियां पहले ही परेशानी से जूझ रही हैं। चीन का मौजूदा बिजली संकट उनकी समस्या और बढ़ा सकता है।

उद्यमियों ने सरकार को चेताया

चीन के उद्यमियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर बिजली संकट से जल्द निजात नहीं मिली तो चीन के इकोनामिक पावर हाउस माने जाने वाले तीन बड़े प्रांत में आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हो सकती हैं। चीन के सिर्फ तीन प्रांत उसकी जीडीपी में एक तिहाई योगदान करते हैं।

दुनिया भर पर असर

चीन में अगर बिजली संकट जल्द दूर नहीं हुआ तो दुनियाभर में क्रिसमस और नए साल के मौके पर स्मार्टफोन, टीवी और दूसरे गैजेट्स खरीदने का इंतजार कर रहे लोगों की उम्मीदों पर पानी फिर सकता है। एप्पल और टेस्ला जैसी कंपनियों के अलग-अलग सप्लायर को भी बिजली संकट की वजह से काम रोकना पड़ा है। चीन की फैक्ट्री के लिए मौजूदा समय सबसे व्यस्त दिनों में एक माना जाता है लेकिन बिजली संकट के कारण इन दिनों लोग खाली बैठे हैं और फैक्टरी में ताला लग रहा है। चीन का यह आर्थिक नुकसान दुनिया भर के बाजार पर असर डाल सकता है।

आखिर चीन क्यों झेल रहा है बिजली की दिक्कत?

चीन से बिजली की इतनी बड़ी

दिक्कत की खबर आने से एक बात जानने की उत्सुकता जरूर बढ़ी होगी कि आखिर वहां ऐसा क्यों हो रहा है? यह वही चीन है, जहां इस साल अगस्त में जितनी बिजली का उत्पादन हुआ था, वह पिछले साल की तुलना में करीब 10.1 फीसदी अधिक थी। वहीं अगर 2019 से तुलना करें तो आंकड़ा करीब 15 फीसदी अधिक था। दरअसल, कोरोना के बाद चीन में औद्योगिक गतिविधियां तेजी से बढ़ी हैं, जिसके चलते बिजली की मांग में तगड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है।

कोयला भी है इसकी एक बड़ी वजह

औद्योगिक गतिविधियां बढ़ने पर अमूमन मांग को कोयला जलाकर पूरा किया जाता है, लेकिन कुछ विवाद के चलते ऑस्ट्रेलिया से कोयले की सप्लाई घटा दी गई है। वहीं चीन की स्थानीय कोयला खदानों में सुरक्षा का ध्यान रखते हुए प्रोडक्शन को कम कर दिया गया है। इतना ही नहीं, दुनिया भर में नेचुरल गैस की कमी भी से भी चीन में बिजली की दिक्कत बढ़ी है, क्योंकि अचानक बढ़ी मांग को पूरा करने के जरिए जरूरी संसाधन उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। देखा जाए तो मौजूदा हाल चीन ही दुनिया में सबसे अधिक प्रदूषण कर रहा है। चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का टारगेट है कि वह 2030 तक चीन में कार्बन डाई ऑक्साइड का उत्सर्जन देश 65 फीसदी तक घटाना है। कोयले के कम इस्तेमाल की एक ये भी बड़ी वजह है।

फैक्ट्री के बाथरूम के दरवाजे पर महिला-पुरुष का मार्क नहीं है, आपको हो सकती है तीन साल की जेल

नई दिल्ली। पिछले कुछ सालों में भारत में कारोबार करने की स्थिति या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में काफी सुधार दर्ज किया गया है। इस वजह से सरकार से लेकर प्रशासनिक अधिकारी तक अपनी पीठ थपथपाने से बाज नहीं आते। इसके बाद भी भारत में कारोबार कर रहे लोगों के लिए स्थितियां बहुत आसान नहीं हुई है। अमेरिकी अस्पताल स्काई डाइविंग से 10 गुना खतरनाक, मेडिकल लापरवाही से 200 में एक की मौत.. इसलिए जरूरी है आयुष्मान भारत - डिजिटल हेल्थ मिशन

अगर आप भारत में कारोबार कर रहे हैं तो फैक्ट्री एक्ट 1948 के नियमों के हिसाब से किसी कारोबारी को टॉयलेट के दरवाजे पर जेंडर मार्किंग नहीं होने की स्थिति में 1 से 3 साल की सजा हो सकती है।

कुछ सुधरी है हालत

अगर आप भारत में कारोबार कर रहे हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि ऐसे 26134 कानून हैं जिनका पालन नहीं करने

की स्थिति में आप को जेल भेजा जा सकता है। साल 2019 में जब वर्ल्ड बैंक ने डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जारी की तो भारत इज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में 63 में नंबर पर आया था। साल 2015 तक 190 देशों की सूची में भारत 142वें स्थान पर था। सिर्फ 5 साल में भारत ने करीब 80 अंक की छलांग लगाकर ऊपर पहुंच बनाई है। इसका मतलब यह है कि भारत में कारोबार करना अब लोगों के लिए आसान हुआ है।

बहुत कुछ करना अभी बाकी

विशेषज्ञों का कहना है कि इज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग सुधरने के साथ भारत में कई सुविधाएं बढ़ी हैं। साल 2014 तक भारत इस मामले में दुनिया के सबसे खराब देशों में शामिल था। साल 2020 में भारत की रैंकिंग काफी बेहतर हुई है। भारत में कारोबार में आसानी के मामले में कई बदलाव हुए हैं और उनका असर भी देखा जा रहा है, लेकिन अब भी इस मामले में बहुत कुछ किया जाना बाकी है।अगर भारत में किसी कारोबार को रजिस्टर करने का नंबर आता हो तो उस में भारत की रैंकिंग 136 है।

रैंकिंग में सुधार नहीं

अगर बात भारत में प्रॉपर्टी को रजिस्टर कराने की हो तो दुनिया के 190 देशों में इसकी रैंकिंग 154 है। टैक्स चुकाने के मामले में भारत की रैंकिंग 115 और कॉन्ट्रैक्ट लागू कराने के मामले में भारत की रैंकिंग 163 है। भारत में किसी कमर्शियल झगड़े को निपटाने में इस समय औसतन 1445 दिन लगते हैं। नया कारोबार रजिस्टर कराने में अब भी भारत में महीनों का समय लगता है।

फैक्ट्री शुरू करना हो तब?

अगर आप कोई फैक्ट्री शुरू करना चाहते हैं तो आपको 6200 से अधिक लाइसेंस रजिस्ट्रेशन परमिशन और कंसेंट ऑर्डर लेने पड़ते हैं। एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चलाने के लिए किसी एमएसएमई को 100 से 1000 कंप्लायंस का पालन करना पड़ता है। इसके साथ ही कई बार उन्हें 20 से 40 इंस्पेक्टर से मंजूरी लेनी पड़ती है। भारत में कारोबार करने के लिए उद्यमियों को अब भी पांच अलग-अलग कंसलटेंट से कंप्लायंस का पालन करने के लिए लाखों रुपये की फीस भरनी पड़ती है। 21वीं सदी के 21 साल में भी यह सच्चाई है। भारत इज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में अपनी लगातार सुधार रहा हो लेकिन देश में कारोबार करने की स्थितियों में बहुत सुधार नहीं आया है।

सिंगापुर की आबादी घटकर 50.45 लाख रह गई, 1970 के बाद सबसे तेज गिरावट

सिंगापुर। एजेंसी

सिंगापुर की कुल आबादी इस साल जून में 4.1 प्रतिशत घटकर 50.45 लाख रह गई, जिसका मुख्य कारण कोविड-19 यात्रा प्रतिबंधों के बीच अनिवासियों की संख्या में गिरावट हो सकता है।, मंगलवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, सरकार द्वारा 1970 में इस तरह के आंकड़े एकत्र करना शुरू करने के बाद से यह सबसे तेज गिरावट है। अनिवासी आबादी में गिरावट कोविड-19 और अनिश्चित आर्थिक माहौल के कारण यात्रा प्रतिबंधों के कारण और विदेशी रोजगार में कमी के कारण थी। संक्षिप्त रिपोर्ट में वार्षिक जनसंख्या के आंकड़े प्रकाशित करने वाले राष्ट्रीय आबादी और प्रतिभा विभाग ने कहा कि 1970 में सरकार द्वारा ऐसे आंकड़े एकत्र करना शुरू करने के बाद से दोनों नागरिक और स्थायी निवासी (पीआर) आबादी में साल दर साल गिरावट आती गई। 'चैनल न्यूज एशिया' ने आंकड़ों के हवाले से कहा कि विशेष रूप से, नागरिकों की संख्या 0.7 प्रतिशत गिरकर 35 लाख हो गई, जबकि स्थायी निवासी संख्या 6.2 प्रतिशत गिरकर 4,90,000 हो गई। राष्ट्रीय आबादी और प्रतिभा विभाग ने कहा, 'वैश्विक महामारी के दौरान यात्रा प्रतिबंध 2021 में नागरिकों और स्थायी निवासी की संख्या को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक रहा क्योंकि ज्यादा नागरिक और स्थायी निवासी लगातार 12 माह या ज्यादा वक्त तक विदेशों में रह रहे हैं जिन्हें निवासी जनसंख्या का हिस्सा नहीं माना गया।' इसमें कहा गया कि कुछ ही लोग पिछले साल नये नागरिक या स्थायी निवासी बने, संभवतः यात्रा प्रतिबंध के कारण और कोविड-19 के कारण संचालन संबंधी सीमाओं के कारण। अनिवासी आबादी में 10.7 प्रतिशत की सबसे बड़ी गिरावट देखी गई और यह 14.7 लाख तक पहुंच गई।

चीन में बिजली संकट तो ब्रिटेन में पेट्रोल की भारी कमी से हड़कंप

अर्थव्यवस्था को लग रहा झटका

मुंबई। आईपीटी नेटवर्क

कोरोना महामारी के संकट के बीच चीन में बिजली और ब्रिटेन में पेट्रोल की भारी कमी से हड़कंप मचा है। चीन में बिजली संकट होने से आम लोगों के साथ-साथ कई बड़ी कंपनियों के काम पर भी असर पड़ा है। वहीं ब्रिटेन में पेट्रोल पंपों के बाहर भारी भीड़ उमड़ रही है। कई पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल खत्म हो गया है। चीन के उत्तर-पूर्व इलाकों में बिजली का भारी संकट पैदा हो गया है। यहां घरों में लोग अंधेरे में रह रहे हैं। जबकि कई फैक्ट्रियों में काम बंद करना पड़ा है। कई मॉल व दुकानें भी बंद हो चुकी हैं। हालांकि कुछ दुकानें मोमबत्ती की रोशनी में संचालित हो रही हैं।

सर्दियों के आगमन के बीच उत्तर-पूर्व के निवासियों ने सोशल मीडिया पर बिजली कटौती की जानकारी दी। इस दौरान निवासियों ने सरकार से जल्द बिजली आपूर्ति बहाल करने की अपील की। वहीं पिछले हफ्ते से ही इन इलाकों में पीक आवर्स के दौरान कटौती की जा रही है। ऐसे में चांगचुन, झेझियांग जैसे कई इलाकों में सरकार ने बिजली काटने की घोषणा कर दी है। साथ ही इन प्रांत के लोगों से भी सरकार ने कहा है कि वह अपने घरों में ऐसे उपकरणों का इस्तेमाल ना करें जो अधिक बिजली की खपत करते हैं। बिजली संकट से चीन की कंपनियों पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एप्पल और टेस्ला जैसी दिग्गज कंपनियों के बिजनेस पर असर पड़ रहा है। दरअसल इन कंपनियों के कुछ सप्लायर्स को बिजली की कमी के चलते अपने कुछ प्लांट पर काम रोकना पड़ा है।

वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित होगी

कोरोना महामारी से बेहाल उद्योग क्षेत्र के लिए चीन के बिजली संकट ने एक और जोखिम पैदा कर दिया है। इससे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के प्रभावित होने की संभावना है। पहले ही निर्माताओं को प्रोसेसर चिप्स की मौजूदा कमी, शिपिंग में व्यवधान और यात्रा और व्यापार के वैश्विक बंद के अन्य प्रभावों का सामना करना पड़ रहा है। बिजली संकट के चलते यहां एप्पल, टेस्ला जैसी कंपनियों में भी काम बंद हो गया है। ऐसे में दुनिया भर में इसका असर पड़ने के आसार हैं। क्रिसमस से पहले स्मार्टफोन और उपकरणों सहित सामानों की कमी हो सकती है। इसके अलावा वैश्विक बाजार में कपड़ों, खिलौनों व मशीनों के पुर्जों की सप्लाई पर भी असर पड़ सकता है।

अर्थव्यवस्था को झटका

बिजली की किल्लत और उत्पादन में तेज गिरावट के असर से चीन

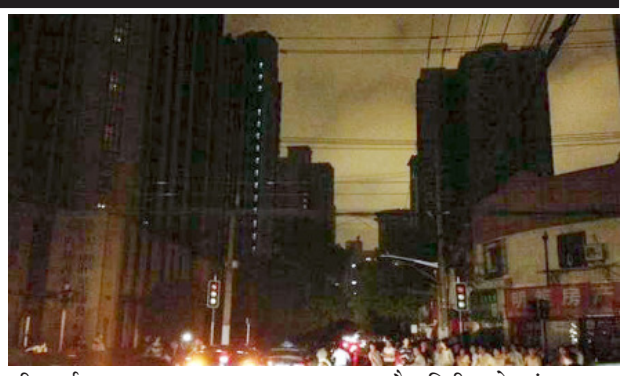

की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ सकता है। वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली वैश्विक निवेश बैंकिंग, सिक्योरिटीज व इंवेस्टमेंट मैनेजमेंट फर्म गोल्डमैन सैक्स ने चीन की जीडीपी वृद्धि के अनुमान को कम किया है। गोल्डमैन सैक्स का अनुमान है कि इस साल 2021 में चीन की अर्थव्यवस्था 7.8 फीसदी की दर से बढ़ सकती है जबकि इसके पहले यह आकलन 8.2 फीसदी का था।

ब्रिटेन ईंधन आपूर्ति सुधारने के लिए सेना की मदद लेगा

ब्रिटेन सरकार ने ट्रक चालकों की कमी के कारण ईंधन आपूर्ति में हुई कमी को सुधारने के लिए सेना की मदद लेने का फैसला किया है। सरकार ने समस्या से निपटने के लिए सेना के जवानों को तैयार रहने को कहा है। ब्रिटेन में ईंधन की कमी की आशंका के बीच पेट्रोल पंपों पर वाहनों की कतारें लग गईं। कई यूनियन ने मांग की थी कि ईंधन आपूर्ति के लिए आपात सेवा में लिप्त कर्मचारी मुहैया करवाए जाएं। जिसके बाद सरकार ने कहा कि उसने ब्रिटेन की सेना के चालकों को तैयार रखा है। ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें ईंधन की आपूर्ति करने के लिए तैनात किया जा सके। इस बीच, शुक्रवार से ही ब्रिटेन के आसपास कई गैस स्टेशनों पर वाहनों की लंबी कतारें लगी रहीं, जिससे व्यस्त सड़कों पर जाम लग गया है।

पेट्रोल के लिए मारपीट

इंपीरियल कॉलेज लंदन के प्रोफेसर डैनी ऑल्टमैन ने ट्वीट करके पेट्रोल खत्म होने के बाद एक लड़ाई देखने का जिक्र किया है। उन्होंने बताया कि मेरे पीछे खड़े एक आदमी ने गार्ड को मारना शुरू कर दिया। इसके बाद 8-10 लोगों में हाथापाई शुरू हो गई और लातों, घूसों से मार पिटाई हुई। वहीं साउथ वेल्स के माइस्टेग में ऑयल 4 वेल्स के डायरेक्टर कॉलिन ऑवेन्स का कहना है कि उनके गैराज में आमतौर पर रोजाना 20 से 30 हजार लीटर ईंधन बेचा जाता है। लेकिन बीते 24 घंटों में 1 लाख लीटर तेल बिक चुका है।

इसलिए पैदा हुआ संकट

- कोयला आपूर्ति में कमी और सख्त उत्सर्जन मानकों के कारण चीन में बिजली की कमी हो रही।
- चीन ने जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए 2021 में तीन फीसदी की कटौती का लक्ष्य रखा है।
- इसके चलते स्थानीय कोयला खदानों में उत्पादन को कम कर दिया गया है।
- साथ ही ऑस्ट्रेलिया से होने वाली कोयले की आपूर्ति में भी दोनों देशों में तनाव के चलते कमी आई है।

दो तिहाई पंपों पर ईंधन नहीं

करीब 5,500 स्वतंत्र पेट्रोल पंपों का प्रतिनिधित्व करने वाले पेट्रोल रिटेलर्स एसोसिएशन ने रविवार को कहा कि करीब दो तिहाई स्टेशनों पर ईंधन नहीं है। ऐसे में वाहनों में ईंधन भरवाने के लिए लोगों की स्टेशनों पर भीड़ उमड़ पड़ी है। इसमें सबसे अधिक प्रभावित ब्रिटेन के शहरी इलाके हैं। जबकि उत्तरी आयरलैंड में इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। एसोसिएशन ने इसके लिए जिम्मेदार लोगों का घबराकर इसे खरीदना बताया है।

देश में पर्याप्त मात्रा में ईंधन : सरकार

कारोबारी मामलों के मंत्री क्वासी क्वार्टेंग ने बताया कि ब्रिटेन के पास बड़ी मात्रा में ईंधन है। उन्होंने कहा कि हालांकि हम पेट्रोल पंपों पर आपूर्ति श्रृंखला में आ रही परेशानी से अवगत हैं और प्राथमिकता के साथ इससे निपटने के लिए कदम उठा रहे हैं। वहीं शेल, एक्सॉनमोबिल और ग्रीनर्जी जैसी तेल कंपनियां यह कह चुकी हैं कि देश में पेट्रोल की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा है कि तेल की सप्लाई का दबाव अस्थाई तौर पर ग्राहकों की मांग में बढ़ोतरी के कारण देखा जा रहा है न कि देश में तेल की कमी के कारण।

ट्रक ड्राइवरों की कमी से संकट

ब्रिटेन में ट्रक ड्राइवरों की कमी के चलते ईंधन आपूर्ति का संकट पैदा हुआ है। ऐसा अनुमान है कि ब्रिटेन में एक लाख से अधिक ट्रक ड्राइवरों की कमी है। इसके कारण हालिया महीनों में बहुत से उद्योगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इनमें सुपरमार्केट्स से लेकर फास्ट फूड चेन्स शामिल हैं। पूरे यूरोप में हेवी गुड्स व्हीकल (एचजीवी) ड्राइवरों की भारी कमी है। लेकिन इसमें भी इस समस्या से सबसे अधिक प्रभावित ब्रिटेन हुआ है। ब्रेग्जिट के बाद कई यूरोपीय देशों के ड्राइवरों ने अपने देश वापस लौटना ठीक समझा या फिर वे कहीं और काम करने लगे हैं। क्योंकि सीमा पर एक अतिरिक्त नौकरशाही हो गई है और इससे उनकी आय पर फर्क पड़ा है। वहीं कोरोना महामारी के कारण भी कई ड्राइवर अपने घर लौटे हैं और उनमें से कुछ ही वापस आ पाए हैं।

एपीएसईज़ेड ने गंगावरम पोर्ट का 6,200 करोड़ रुपये में अधिग्रहण करके भारत के पूर्वी दूर-दराज के इलाकों को पूरी तरह से अनलॉक किया

जीपीएल में आंध्र प्रदेश सरकार की हिस्सेदारी की खरीद को पूरा किया। बोर्ड ने एपीएसईज़ेड के साथ जीपीएल के विलय को मंजूरी दी

अहमदाबाद। भारत की सबसे बड़ी निजी पोर्ट्स एवं लॉजिस्टिक्स कंपनी और डायवर्सिफायड अदाणी ग्रुप की प्रमुख परिवहन शाखा, अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन लिमिटेड (एपीएसईज़ेड), ने 645 करोड़ रुपये में आंध्र प्रदेश सरकार (जीओएपी) की 10.4इ हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया। एपीएसईज़ेड और जीपीएल के बोर्ड ने एपीएसईज़ेड के साथ जीपीएलके विलय को भी मंजूरी दे दी है। यह मंजूरी जीपीएल के 120 रुपये प्रति शेयर के मूल्यांकन और एपीएसईज़ेड के 754.8 प्रति शेयर उचित मूल्य को ध्यान में रखते हुए दी गई है, जिसके परिणामस्वरूप जीपीएल में डीवीएस राजू एंड फैमिली की 58.1इ हिस्सेदारी के लिए जीपीएल के 1,000 शेयरों के लिए एपीएसईजेड के 159 शेयरों का स्वैप रेशियो है। विलयकी नियत तारीख 1 अप्रैल 2021 है और यह एनसीएलटी की मंजूरी के अधीन है। विलय 31 मार्च 2022 तक पूरा होने की उम्मीद है। एपीएसईज़ेड पोर्टफोलियो के हिस्से के रूप में जीपीएल मजबूत विकास क्षमता के साथ ऋण मुक्त है। ट्रांजैक्श न 16,200 करोड़ रुपये के इक्विटी मूल्य पर पूरा किया गया है और जिसमें । 8.8 गुना का ईवी/ वित्त वर्ष 21 ईबीआईटीडीए मल्टिप्लावयर अंतर्निहित है और परिणामस्वरूप एपीएसईज़ेड वित्त वर्ष 21 आय में । 7इ की ईपीएस अभिवृद्धि होती है। जीपीएल 64 एमएमटी क्षमता वाला नॉन-मेजर पोर्ट है जो आंध्र प्रदेश सरकार (जीओएपी) से रियायत के तहत 2059 तक के लिए स्थापित किया गया है और यह पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी और मध्य भारत के 8 राज्यों के दूर-दराज के इलाकों के लिए गेटवे पोर्ट है। इस अधिग्रहण से कई नए बाजारों में एपीएसईज़ेड की पहुंच को महत्वपूर्ण बढ़त हासिल होगी। 200,000 डीडब्ल्यूटी तक के पूरी तरह से लदे सुपर केप आकार के जहाजों को संभालने में सक्षम, एक गहरे ड्राफ्ट आधुनिक बहुउद्देश्यीय पोर्ट के रूप में, जीपीएल कोयला, लौह अयस्क, उर्वरक, चूना पत्थर, बॉक्साइट, चीनी, एल्यूमिना, और स्टील सहित शुष्क और थोक वस्तुओं के विविध मिश्रण को संभालने में सक्षम है। एपीएसईज़ेड के सीईओ एवं पूर्णकालिक निदेशक श्री करण अदाणी ने कहा कि 'हम आंध्र प्रदेश के औद्योगीकरण में तेजी लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमने पोर्ट्स नेटवर्क बनाना जारी रखा है, जिससे हमें अपने ग्राहकों को बेजोड़ सेवाएं प्रदान करने के लिए लॉजिस्टिक्स क्षमताओं का एक एकीकृत नेटवर्क बनाने की सुविधा मिलती है। गंगावरम इस नेटवर्क का एक प्रमुख हिस्सा है, जो भारत के सबसे तेजी से बढ़ते राज्यों में से एक राज्य मेंस्थित है। हम जीपीएल के विकास की संभावनाओं को लेकर उत्साहित हैं, जो हमारी पूर्वी तट विस्तार रणनीति का मूल मंत्र है। जीपीएल हमें बड़े पैमाने पर दूर-दराज के इलाकों के बाजार में, जो फिलहाल उपयोग में नहीं हैं, अभूतपूर्व पहुंच की सुविधा प्रदान करने के लिए फायदेमंद स्थिति में है।'

चिप संकट से नए उत्पादों में विलंब, जोखिम से निपटने के उपाय कर रहे हैं : सिएमा

नयी दिल्ली। एजेंसी

घरेलू उपकरण और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग सेमीकंडक्टर और चिप के संकट से जूझ रहा है। उद्योग के निकाय उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स एवं उपकरण विनिर्माता संघ (सिएमा) ने कहा कि यह संकट न केवल 2022 तक बना रहेगा बल्कि इसके 2023 तक भी जाने की आशंका है। सिएमा के अध्यक्ष कमल नंदी ने कहा कि कई विनिर्माता अपने उत्पादों में सामग्री के रूप में चिप का इस्तेमाल करते हैं। चिप के संकट से उनकी क्षमता प्रभावित हो रही है। इससे नए उत्पादों की पेशकश में भी विलंब हो रहा है। नंदी ने कहा कि चिप की कमी और लौह उत्पाद बढ़ने से क्षेत्र में कीमतों में आई गिरावट के प्रभाव समाप्त हो गया है। उन्होंने कहा कि सेमीकंडक्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक कलपुर्जों की कमी की वजह से थोड़े समय के लिए कंट्रोलर की कमी हो सकती है। नंदी ने पीटीआई-भाषा से कहा कि त्योहारों के दौरान मांग को पूरा करने के लिए हम निकट भविष्य के जोखिमों से निपटने को उचित उपाय किए हैं। सेमीकंडक्टर और चिप का इस्तेमाल उद्योग द्वारा बनाए जाने वाले उपकरणों की श्रृंखला के लिए महत्वपूर्ण कलपुर्जों मसलन माइक्रो कंट्रोलर, ऑप्टोकपलर, पावर रिले, स्विच, वैरिस्टर और कनेक्टर के विनिर्माण में होता है। नंदी ने कहा कि हमारा अनुमान है कि यह संकट 2022 में भी बना रहेगा और 2023 तक जाएगा।

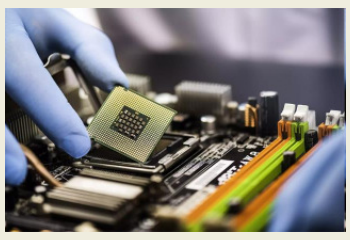

सर्वपितृ अमावस्या पर श्राद्ध करने के 5 फायदे, पितृदोष से मिलती है मुक्ति

आश्विन माह की कृष्ण अमावस्या को सर्वपितृ मोक्ष श्राद्ध अमावस्या, 'पितृविसर्जनी अमावस्या', 'महालय समापन' या 'महालय विसर्जन' भी कहते हैं। श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान आदि कर्म करने के बाद भोजन कराए जाने की परंपरा है। 6 अक्टूबर 2021 को सर्वपितृ अमावस्या है। आओ जानते हैं कि इस दिन क्या करने से क्या लाभ होगा।

1. शास्त्र कहते हैं कि 'पुन्नामनरकात् त्रायते इति पुत्रः' जो नरक से त्राण (रक्षा) करता है वही पुत्र है। इस दिन किया गया श्राद्ध पुत्र को पितृदोषों से मुक्ति दिलाता है। अतः पूर्वजों के निमित्त शास्त्रोक्त कर्म करें जिससे उन मृत प्राणियों को परलोक अथवा अन्य लोक में भी सुख प्राप्त हो सके।

2. अगर कोई श्राद्ध तिथि में किसी कारण से श्राद्ध न कर पाया हो या फिर श्राद्ध की तिथि मालूम न हो तो सर्वपितृ श्राद्ध अमावस्या पर श्राद्ध किया जा सकता है। सर्वपितृ अमावस्या उन पितरों के लिए भी होती है जिनके बारे में आप नहीं जानते हैं। अतः सभी जाने और अनजाने पितरों हेतु इस दिन निश्चित ही श्राद्ध किया जाना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन सभी पितर आपके द्वार पर उपस्थित हो जाते हैं। ऐसे में उचित विधि से श्राद्ध करने से सभी पितृ प्रसन्न होकर आपके जीवन में खुशियां भर देते हैं।

3. इस श्राद्ध में गोबलि, श्वानबलि, काकबलि, पिप्लपादबलि और देवादिबलि कर्म करें। अर्थात इन सभी के लिए विशेष मंत्र बोलते हुए भोजन सामग्री निकालकर उन्हें ग्रहण कराई जाती है। अंत में मछली और चींटियों के लिए भोजन सामग्री पत्ते पर निकालने के बाद ही भोजन के लिए थाली अथवा पत्ते पर ब्राह्मण हेतु भोजन परोसा जाता है। इस दिन सभी को अच्छे से पेटभर भोजन खिलाकर दक्षिणा दी जाती है। ऐसा करने से आपके जीवन के संकट दूर होते हैं, कर्ज उतर जाता है, कोई रोग हो तो वह ठीक हो जाता है और घर में शांति, सुख और समृद्धि का वास होता है।

4. सर्वपितृ अमावस्या के दिन पितरों की शांति के लिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए गीता के सातवें अध्याय का पाठ करने का विधान भी है। सर्वपितृ अमावस्या पर पीपल की सेवा और पूजा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। स्टील के लोटे में, दूध, पानी, काले तिल, शहद और जौ मिला लें और पीपल की जड़ में अर्पित कर दें। ऐसा करने से भगवान विष्णु और श्रीकृष्ण प्रसन्न होते हैं।

5. इस दिन शास्त्रों में मृत्यु के बाद और्ध्वदैहिक संस्कार, पिण्डदान, तर्पण, श्राद्ध, एकादशाह, सपिण्डीकरण, अशौचादि निर्णय, कर्म विपाक आदि के द्वारा पापों के विधान का प्रायश्चित कहा गया है। ऐसा करने से अगले पिछले सभी जन्मों के पाप कट जाते हैं और व्यक्ति मोक्ष पाता है।

पितृ पक्ष की खास बातें

अगर श्राद्ध कर्म नहीं कर पा रहे हैं तो जरूरतमंद लोगों को खाना खिलाएं और दान-पुण्य करें

अभी पितृ पक्ष चल रहा है। पितरों के लिए श्राद्ध कर्म करने का ये पक्ष 6 अक्टूबर तक चलेगा। इन दिनों में पितरों के लिए पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध करने की परंपरा है। उज्जैन के ज्योतिषाचार्य पं. मनीष शर्मा के अनुसार अगर कोई व्यक्ति श्राद्ध नहीं कर पा रहा है तो उसे किसी जरूरतमंद व्यक्ति को खाना खिलाना चाहिए। किसी मंदिर में, गौशाला में या गरीब बच्चों को धन और अनाज का दान करना चाहिए। किसी पवित्र नदी में स्नान करें और काले तिल बहाएं।

■पितृ पक्ष में किसी व्यक्ति की मृत्यु तिथि के अनुसार तर्पण करने का विधान है। इन दिनों में किसी पवित्र नदी में दूध, जौ, चावल, काले तिल बहाकर तर्पण किया जाता है।

■पितरों के लिए पितृ पक्ष में पिंडदान किया जाता है। पिंड पके हुए चावल, दूध और काले तिल मिलकर बनाए जाते हैं। इन पिंडों को मृत व्यक्ति के शरीर का प्रतीक माना जाता है।

■जो लोग पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध कर्म नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें किसी ब्राह्मण या गरीब व्यक्ति धन और अनाज का दान करना चाहिए। घर में बैठाकर भोजन करवाना चाहिए। किसी गौशाला में या मंदिर में धन, हरी घास और पूजन सामग्री का दान करें। पितरों के नाम से प्याऊ खुलवाएं।

■अगर श्राद्ध नहीं कर पा रहे हैं तो किसी नदी में काले तिल डालकर तर्पण करें। पितरों का ध्यान करें। स्नान के बाद कम से कम एक मुट्ठी काले तिल का दान करें।

■रोज सुबह जल्दी उठें और स्नान के बाद सूर्य को जल चढ़ाएं। सूर्यदेव से पितरों की आत्मा को शांति देने की प्रार्थना करें। इसके बाद रोज पीपल पर भी जल चढ़ाना चाहिए।

ध्यान रखें इन दिनों में गलत कामों से बचना चाहिए। जो लोग पितृ पक्ष में अधार्मिक कर्म करते हैं, उन्हे पिंडदान, तर्पण आदि पुण्य कर्मों का फल नहीं मिल पाता है। पितृ पक्ष में गीता, रामायण, गरुड़ पुराण का पाठ करना चाहिए। इन ग्रंथों को पूरा नहीं पढ़ सकते तो रोज इनका थोड़ा-थोड़ा हिस्सा पढ़ सकते हैं। ग्रंथों में बताई गई बातों को जीवन में उतारने की कोशिश करनी चाहिए।

सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या पर इन 10 लोगों को कराएं भोजन

श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान आदि कर्म करने के बाद भोजन कराए जाने की परंपरा है। 6 अक्टूबर 2021 को सर्वपितृ अमावस्या है। आओ जानते हैं कि इस दिन किन लोगों को कराना चाहिए भोजन।

1. गाय : गाय में सभी देवी और देवता निवास करते हैं। अग्निग्रास के बाद गाय को भोजन दिया जाता है।

2. कौआ : कौए को पितरों का रूप ही माना जाता है। कहते हैं पितर कौए के रूप में आकर भी भोजन ग्रहण कर लेते हैं।

3. कुत्ता : कुत्ते को यम का दूत कहते हैं। इसे भी पितरों का रूप माना जाता है।

4. चींटी : चींटी को भी आटा में शक्कर मिलाकर डालें और इसके साथ ही घर में पितरों के लिए जो भोजन बना है उसे भी अर्पित करें।

5. मछली : मछली को भी आटा की गोली बनाकर डालें और इसके साथ ही घर में पितरों के लिए जो भोजन बना है उसे भी अर्पित करें।

6. गरीब : गरीबों को भोजन कराना सबसे बड़ा पुण्य है। श्राद्ध का भोजन ब्राह्मण भोज के अलावा किसी भूखे या गरीब को भी खिलाना चाहिए। सबसे पहले द्वार आया गरीब या मंदिर के समक्ष बैठे गरीब को यह भोजन खिलाना चाहिए।

7. ब्राह्मण : इस दिन 16 ब्राह्मण को अच्छे से पेटभर भोजन खिलाकर दक्षिणा दी जाती है। ब्राह्मण का निर्वसनी होना जरूरी है।

8. जमाई : घर के जमाई को भोजन खिलाना भी जरूरी है।

9. भांजा : कहते हैं कि एक भानेज 100 ब्राह्मणों के बराबर होता है।

10. नाती : लड़की का लड़का या लड़की आपकी नाती होती है।

11. इसके अलावा देवता, पितर, पीपल और अग्नि के लिए अलग से भोजन

निकाला जाता है। देवताओं और पितरों के भोग को अग्नि को समर्पित किया जाता है और पीपल के भोग को उस वृक्ष के नीचे रखा जाता है। उपरोक्त सभी से पहले अग्निदेव को अग्निग्रास देते हैं।

जब भी रोटी बनाएं तो पहली रोटी अग्नि की, दूसरी रोटी गाय की और तीसरी रोटी कुत्ते की होती है। पहली रोटी मूल रूप से बहुत ही छोटी बनती है। अंगूठे के प्रथम पोर के आकार की। इस रोटी को अग्नि में होम कर दिया जाता है। अग्नि में होम करते वक्त इसके साथ अन्य जो भी बनाया है उसे भी होम कर दिया जाता है। पांच तरह के यज्ञों में से एक है देवयज्ञ जिसे अग्निहोत्र कर्म भी कहते हैं, यही देवबलि भी है।

पितृ पक्ष 6 अक्टूबर तकःपितरों की संतुष्टि के लिए ग्रंथों में बताया है घी, गुड़ और तिल सहित दस चीजों के दान का विधान

पितृ पक्ष 6 अक्टूबर तक रहेगा। इस दौरान पिंडदान, तर्पण और पंचबली के साथ श्राद्ध करने से पितर संतुष्ट होते हैं। लेकिन इन दिनों कई तरह के दान करने की भी परंपरा है। जो कि धर्म ग्रंथों में बताए गए हैं। ग्रंथों में मृतात्मा और पितरों की संतुष्टि के लिए जो दान बताए हैं उनमें से कई चीजें आसानी से घर में मिल जाती हैं।

बनारस, पुरी और उज्जैन के विद्वानों का कहना है कि ये जरूरी नहीं कि हमेशा महंगी चीजों का ही दान किया जाए। श्रद्धा और आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर घर में जो चीजें मिल जाए उनसे हम अपने पितरों के निमित्त दान कर सकते हैं। जिससे घर में सुख-समृद्धि आती है और हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं।

पितृ दोष से मुक्ति और आर्थिक संपन्नता के लिए दान

पुरी के ज्योतिषाचार्य डॉ. गणेश मिश्र बताते हैं कि श्राद्ध पक्ष में किए गए दान से पितर संतुष्ट तो होते हैं। इससे पितृ दोषों से मुक्ति मिलने लगती है। साथ ही आर्थिक संपन्नता भी मिलती है। पितरों के लिए जो चीजें दान करनी चाहिए उनका जिक्र पुराणों और अन्य धर्म ग्रंथों में मिलता है। इनमें से ज्यादातर चीजें तकरीबन हर घर में आसानी से मिल जाती हैं।

ग्रंथों में बताए गए आठ और दस महादान

निर्णयसिंधु और गरुड़ पुराण में महादान की जानकारी दी गई है। इन ग्रंथों में बताया गया है कि श्राद्ध या मृत्यु के बाद कौन सी चीजों का दान किया जाना चाहिए। जिससे मृतआत्मा या पितरों का संतुष्टि मिले। इसके लिए इन ग्रंथों में दस तरह के महादान बताए गए हैं। लेकिन इतना न कर पाएं तो आठ तरह की खास चीजों का दान कर के ही अष्ट महादान का भी पुण्य मिल जाता है।

दस महादान

गोभूतिलहिरण्याज्यं वासो धान्यं गुडानि च ।
रौप्यं लवणमित्याहुर्दशदानान्यनुक्रमात् - निर्णय सिन्धु ग्रंथ

अर्थ - गाय, भूमि, तिल, सोना, घी, वस्त्र, धान्य, गुड़, चांदी और नमक इन दस चीजों का दान दश महादान कहलाता है। यह दान पितरों के निमित्त दिया जाता है। किसी कारण से मृत्यु के वक्त न किया जा सके तो श्राद्ध पक्ष में इन चीजों का दान करने का विधान बताया गया है।

अष्ट महादान

तिला लोहं हिरण्यं च कार्पासो लवणं तथा।
सप्तधान्यं क्षितिर्गावो ह्येकैकं पावनं स्मृतम् - गरुड पुराण

अर्थ - तिल, लोहा, सोना, कपास, नमक, सात तरह के धान, भूमि और गाय। इन आठ का दान करना ही अष्ट महादान कहलाता है। इस तरह का महादान मृतात्मा या पितरों को संतुष्टि देने वाला होता है।

अमेरिका में क्रिसमस ट्री की लागत बढी चीन से आने वाला सामान पोर्ट पर अटका

62 कंटेनर जहाजों का विशाल बैकलॉग डॉक करने की प्रतीक्षा में

एजेंसी

लॉस एंजिल्स और लॉन्ग बीच का बंदरगाह परिसर, जो अमेरिका में 40 प्रतिशत कंटेनरों को ले जाता है, वर्तमान में 62 मालवाहक जहाज बंदरगाह में प्रवेश करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह स्थिती शिपिंग अवधि बढने, कोरोना महामारी से प्रेरित खरीदी और श्रम की कमी के संयुक्त कारणों की वजह से है। यह बंदरगाह अमेरिका में आयात के एक तिहाई कंटेनरों के लिए प्रवेश बिंदु के रूप में काम करते हैं, और चीन से आने वाले सामानों के लिए मुख्य आयात केंद्र हैं।

पश्चिमी तट के बंदरगाहों को अगस्त से भारी ट्रैफिक का सामना करना पड़ रहा है, जब रिकॉर्ड तोड़ 44 कंटेनर जहाज इसी तरह के व्यवधानों के कारण तट से दूर फंस गए थे। लॉन्ग बीच पोर्ट अब अपने सर्वकालिक रिकॉर्ड को तोड़ने की गति पर है और इस साल 9 मिलियन कंटेनर इकाइयों की तुलना में प्रक्रिया कर रहा है, 2020 की तुलना में लगभग एक मिलियन अधिक इकाइयाँ कंटेनर आने वाले है।

छुट्टियों के मौसम के लिए अमेरिकी में अचानक खरीदी में उछाल आया है। इसके कारण बड़े पैमाने पर बैकअप में कंटेनर जहाजों की एक रिकॉर्ड संख्या वर्तमान में लॉस एंजिल्स के बंदरगाहों के बाहर इंतजार कर रही है।समाचार एजेंसी के अनुसार लॉस एंजिल्स और लॉन्ग बीच का बंदरगाह परिसर, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में 40 प्रतिशत कंटेनरों को ले जाता है, वर्तमान में 62 मालवाहक जहाज बंदरगाह में प्रवेश करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बंदरगाह के अधिकारियों का कहना है कि देश के सबसे व्यस्त बंदरगाह परिसर में बैकअप आगामी छुट्टियों के मौसम और कोरोना महामारी से प्रेरित खरीदी बढने के कारण है। जो श्रम की कमी के साथ मिलकर बंदरगाह कर्मचारियों को प्रभावित कर रहा है। दक्षिणी कैलिफोर्निया के समुद्री एक्सचेंज जो क्षेत्र में जहाज यातायात को ट्रैक करता है के अनुसार डॉक की प्रतीक्षा कर रहे 62 कंटेनर जहाजों में 42 कंटेनर जहाज शारीरिक रूप से लंगर में और 20 बहाव क्षेत्रों में शामिल हैं। चीन से आने वाले सामानों के लिए मुख्य प्रवेश बिंदु बंदरगाहों पर लगे इस ट्रैफिक जाम ने कृत्रिम क्रिसमस पेड़ों की कीमतों को भी सीधे प्रभावित किया है।

कैलिफ़ोर्निया स्थित एक कृत्रिम पेड़ कंपनी बाल्सम हिल इस साल अपने साढ़े चार फुट ऊंचे ग्रैंड कैन्यन सीडर ट्री को 499 डॉलर में बेच रही है। यह 2020 में उसी पेड़ की लागत से 199 डॉलर अधिक है - केवल 12 महीनों में कीमत में दो-तिहाई की वृद्धि।

बाल्सम हिल के सीईओ मैक हार्मन ने बताया, हमने अपने इतिहास में कभी भी इसके करीब कहीं भी कीमतें नहीं बढ़ाई हैं और कम पैसे कमाएंगे। हरमन ने कहा, हमारे लिए पहली बार कैटलॉग आउट हो गया था और हमारे पास बेचने के लिए कोई उत्पाद नहीं था। हमारे शिपमेंट समय पर नहीं पहुंचे। हम अभी भी यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि उत्पाद कहां हैं। क्या वे अभी भी पानी पर हैं या बंदरगाहों में फंस गए हैं? अगर ऐसा होता रहा, तो हम कारोबार से बाहर हो सकते हैं।

जून में, लॉस एंजिल्स बंदरगाह 12 महीने की अवधि में 10 मिलियन कंटेनर इकाइयों को संसाधित करने वाला पहला पश्चिमी गोलार्ध बंदरगाह बन गया। मरीन एक्सचेंज के कार्यकारी निदेशक किप लाउटिट ने बताया कि आपूर्ति-श्रृंखला आयात की भारी आमद के लिए तैयार नहीं की गई है। समस्या का एक हिस्सा यह है कि जहाज उन जहाजों के आकार से दोगुने या तिगुने हैं जिन्हें हम 10 या 15 साल पहले देख रहे थे। उन्हें उतारने में अधिक समय लगता है। माल डालने के लिए आपको अधिक ट्रकों, अधिक ट्रेनों, अधिक गोदामों की आवश्यकता है।' दक्षिणी कैलिफोर्निया बंदरगाह बिडेन प्रशासन और परिवहन विभाग के साथ काम कर रहे हैं लॉन्ग बीच के मेयर रॉबर्ट गार्सिया ने जहाजों के लिए देरी को कम करने में मदद के लिए ट्विटर पर घोषणा की। लॉन्ग बीच का बंदरगाह एक 24/7 पायलट कार्यक्रम का परीक्षण कर रहा है जो कार्गो पिकअप के घंटों का विस्तार ऐसे समय में करेगा जब क्षेत्र में कम यातायात हो, जिससे तेजी से वितरण की अनुमति मिल सके। पोर्ट ऑफ लॉन्ग बीच के कार्यकारी निदेशक मारियो कोर्डेरो ने एक बयान में कहा, 'हम कार्गो में ऐतिहासिक उछाल के बीच में हैं, और हमारे टर्मिनल ऑपरेटर और अन्य आपूर्ति श्रृंखला भागीदार इसे आगे बढ़ने के लिए अपना सब कुछ दे रहे हैं।' 'हम चौबीसों घंटे संचालन के लिए गेट्स का विस्तार करने की दिशा में पहले कदम के रूप में टीटीआई द्वारा इस पायलट परियोजना का स्वागत करते हैं, और हम अपने कार्गो मालिकों और ट्रकिंग भागीदारों को इस अभिनव कार्यक्रम को आजमाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।'

ई व्हीकल भी किए जाएंगे कबाड़, 15 साल तक चलाए जा सकते हैं इलेक्ट्रिक वाहन

फ्यूल टेक्नोलॉजी में भेदभाव नहीं करती स्क्रैपेज पॉलिसी

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

देश में पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए पेट्रोल-डीजल वाहनों के बजाय इलेक्ट्रिक व्हीकल को बेहतर विकल्प बताया माना रहा है। इसके लिए केंद्र समेत तमाम राज्य सरकारें ई-वाहन को लेकर नई-नई योजनाएं और नीतियां भी लेकर आ रही हैं। ई-वाहन खरीदने के लिए लोगों को प्रोत्साहन राशि के साथ ही कर्ज की सुविधा और छूट भी दी जा रही है। इससे लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए उत्साहित नजर आ रहे हैं। अगर आप भी ई-वाहन खरीदने जा रहे हैं तो जान लें कि इनकी उम्र कितनी होगी? आसान शब्दों में कहें तो यह जानना जरूरी है कि ई-वाहनों को कितने साल तक सड़क पर चलाने के बाद स्क्रैप किया जाएगा।

केंद्र ने नई व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी में बनाईं नई नीतियां

सरकार ने पेट्रोल वाहनों के लिए 15 और डीजल वाहनों के लिए 20 साल की समयसीमा तय की है। हाल में केंद्र की नई व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी में पेट्रोल और डीजल

से चलने वाली गाड़ियों के कबाड़ में शामिल करने को लेकर नई नीतियां बनाई गई हैं। पॉलिसी के मुताबिक, पेट्रोल-डीजल की 15 और 20 साल पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप कर दिया जाएगा। व्यावसायिक वाहन को 15 साल और निजी कार को 20 साल के बाद कबाड़ में डाल दिया जाएगा।

फ्यूल टेक्नोलॉजी में भेदभाव नहीं करती स्क्रैपेज पॉलिसी

इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर दिल्ली के पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वॉटर में सीनियर प्रोग्राम लीड हिमानी जैन ने बताया कि इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर भी स्क्रैपेज के नियम हैं। चूंकि वाहनों को स्क्रैप करने एक समय सीमा के बाद इस्तेमाल से बाहर करने की नीति उसमें इस्तेमाल होने वाली फ्यूल टेक्नोलॉजी में भेदभाव नहीं करती है। इसलिए इलेक्ट्रिक वाहनों को स्क्रैप करने के लिए प्रोत्साहन और प्रक्रिया दूसरे वाहनों जैसी ही है। वे कहती हैं कि कॉमर्शियल इलेक्ट्रिक वाहन, बसें, गाड़?यां 15 साल के बाद कबाड़ बन जाएंगी। यही स्थिति निजी वाहनों को लेकर रहेगी. ऐसे में ईवी खरीदने के लिए सोच रहे लोग बिना किसी चिंता के ये वाहन खरीद सकते हैं।

'अमूल हनी' की शुरुआत

मधुमक्खी पालन को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दे रही सरकार- तोमर

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मंगलवार को राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड (एनबीबी) के साथ मिलकर गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड (जीसीएमएमएफ) द्वारा विकसित एक नया उत्पाद 'अमूल हनी' बाजार में पेश किया। इस पेशकश के बाद तोमर ने कहा कि सरकार छोटे किसानों की आय दोगुनी करने के लिए मधुमक्खी पालन को बढ़ावा दे रही है। इसके लिए करीब 500 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। एक सरकारी बयान में तोमर के हवाले से कहा गया है कि एनबीबी की स्थापना विभिन्न गतिविधियों को संचालित करने के लिए भी की गई थी। उदाहरण के लिए, शहद की गुणवत्ता की जांच के लिए पांच प्रमुख प्रयोगशालाएं और 100 मिनी-शहद परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की जा रही हैं। इसके अलावा, तोमर ने स्थानीय शहद मानकों को सुधारकर वैश्विक स्तर पर लाने और निर्यात को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया। सहकारी मॉडल को कृषि क्षेत्र में सफलता की कुंजी बताते हुए तोमर ने कहा कि सहकारी भावना के साथ काम करने से दूध के क्षेत्र में अमूल की तरह बढ़ने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि अमूल ब्रांड के मालिक जीसीएमएमएफ ने देश में श्वेत क्रांति लाने में बड़ा योगदान दिया है। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा कि किसान न केवल शहद से बल्कि रॉयल जेली जैसे उप-उत्पादों से भी कमा सकते हैं, जिनकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारी मांग और बेहतर कीमतें हैं। इस कार्यक्रम में कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी और शोभा करंदलाजे के साथ-साथ जीसीएमएमएफ के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

ऑडी ने कहा, आयातित इलेक्ट्रिक वाहनों पर शुल्क घटाए सरकार

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

जर्मनी की लक्जरी कार कंपनी ऑडी ने भारत में आयातित कारों पर लगने वाली कर की ऊंची दरों को इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र की वृद्धि के लिए बाधा करार दिया है। कंपनी ने आयातित कारों पर कर की दरों में कटौती का आग्रह किया है। कंपनी ने कहा कि शुल्कों में कुछ राहत से भी वह अधिक वाहन बेच सकेगी और अपने मुख्यालय को ऐसे वाहनों के स्थानीय विनिर्माण के लिए निवेश के प्रति आश्वस्त कर पाएगी। ऑडी की देश में फिलहाल पांच बिजली चालित यानी इलेक्ट्रिक वाहन बेचती है। कंपनी ने कहा कि आयात किये जाने वाले मॉडलों पर कर में कमी से वाहन के मूल्य को कम करने में मदद मिलेगी। साथ ही बाजार में वह एक निश्चित मात्रा में बिक्री के आंकड़े को हासिल कर पाएगी। ऑडी ने कहा कि यदि कंपनी को बाजार में एक निश्चित हिस्सेदारी मिलती है तो वह अपने वैश्विक मुख्यालय को भारत विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए देश में फिर से निवेश करने के लिए मनाने की कोशिश करेगी। ऑडी इंडिया के प्रमुख बलबीर सिंह ढिल्लों ने पीटीआई-भाषा से बातचीत में कहा कि कंपनी देश में आयातित अपने इलेक्ट्रिक वाहनों के पहले सेट को बेच दिया है। उन्होंने कहा, "हाल में भारतीय बाजार में उतारी गई की गई बिजली से चलने वाली ई-ट्रॉन गाड़ी की पहली खेप बिक गई हैं। इससे हमें विश्वास मिला है कि लोग और भारत इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए तैयार है। यह सब हमें ऐसी अधिक से अधिक कारों को पेश करने में मदद कर रहा है।" कंपनी ने पिछले सप्ताह ही दो नई पूर्ण इलेक्ट्रिक चार दरवाजे की कूपे ई-ट्रॉन जीटी और आरएस ई-ट्रॉन जीटी भारत में पेश की है। इसके साथ कंपनी की भारत में बिजली से चलने वाली कुल पांच गाड़ियां हो गई है। हालांकि, उन्होंने कहा कि आयात शुल्क इलेक्ट्रिक वाहनों के रास्ते में बाधक साबित हो रहा है।

ऊपरी तौर से स्वस्थ नौजवानों में हार्ट अटैक एक गहन चिंता का विषयः डॉ. राकेश जैन

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

गत वर्षों में यह देखने में आया है कि ऊपरी तौर से स्वस्थ नौजवानों, खासतौर पर कीर्ति प्राप्त लोगों में हार्ट अटैक की संभावना काफी बढ़ी है, जिसके चलते वे अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार की घटनाएं बहुत बड़ी चिंता का विषय है। इसका कारण क्या हो सकता है? दूसरा प्रश्न दिमाग में यह आता है कि क्या ऊपरी तौर से स्वस्थ दिखने वाले नौजवानों को हार्ट अटैक आना वाकई मेडिकली स्वस्थ है? इसका उत्तर है 'न'....यह बात शहर के जाने-माने सुप्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ, डॉ. राकेश जैन, महावीर हार्ट क्लिनिक तथा डायग्नोस्टिक सेंटर, गीता भवन ने विश्व हृदय दिवस के मौके पर कही है।

दिल की बिमारियों के कारण पूरे विश्व में प्रतिवर्ष लगभग 17 मिलियन लोगों की जान चली जाती है, जो कि कुल मृत्यु दर का 31% हिस्सा है। दिल की बिमारियों में सबसे प्रमुख, दिल की नसों में ब्लॉकेज तथा हार्ट अटैक का आना होता है। आजकल नौजवानों (उम्र 45 वर्ष से कम) खासतौर पर भारतीयों में इसका प्रसार काफी तेजी से बढ़ रहा है, जिसकी अनुपातिक प्रधानता 10-15% है।

डॉ. जैन ने बताया कि हार्ट अटैक के प्रमुख कारण- अधिक उम्र, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हाई कोलेस्ट्रॉल, मोटापा तथा असंतुलित दिनचर्या आदि हैं, जो कि 85-90% तक हार्ट अटैक के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसके अलावा धूम्रपान भी नौजवानों में हार्ट अटैक के लिए एक मुख्य कारक है। नौजवान भारतीयों (उम्र 45 वर्ष से कम) में धूम्रपान की प्रवृत्ति 60-90% तक है, जो कि 45 वर्ष से ज्यादा वर्ष के लोगों से लगभग दोगुना है। धूम्रपान, खासतौर पर पारम्परिक, वंशानुगत तथा वातावरण संबंधी कारकों की उपस्थिति भविष्य में नौजवानों के भीतर हार्ट अटैक की संभावना को प्रबल करती है। धूम्रपान तथा मोटापे के कारण हार्ट अटैक के बाद इससे उबरने में भी काफी परेशानी होती है, इसके साथ ही परिणाम भी विपरीत होते हैं।

एक संतुलित जीवनचर्या, अच्छी नींद, ऐरोबिक, शारीरिक व्यायाम (प्रतिदिन लगभग 45 मिनट), हरी सब्जियाँ तथा फलों का सेवन, बाहरी असंतुलित खाने का त्याग, धूम्रपान का त्याग, इत्यादि दिल की बिमारियों से बचने के सबसे सीधे तथा सरल तरीके हैं। यदि आप किसी बीमारी, जैसे- मधुमेह, ब्लड प्रेशर इत्यादि से ग्रसित हैं, तो आपने डॉक्टर की नियमित निगरानी में दवाइयों का सेवन करें। अपने दिल के स्वास्थ्य को जानने के लिए इसके नियमित चेकअप हेतु अपने हृदय रोग विशेषज्ञ के सम्पर्क में रहे, और संबंधित सलाह का पालन करें।

ज़नवोल्ट ने अपने पार्टनरशिप मॉडल का अनावरण किया

पहले दिन 50+ पार्टनर्स हुए शामिल

गुरुग्राम। आईपीटी नेटवर्क

गुरुग्राम स्थित एनर्जी स्टार्टअप ज़नवोल्ट ने अपने नए पार्टनरशिप मॉडल का अनावरण किया, जो छोटे बिज़नेस की एक्सटेंसिव मार्केटिंग और बिक्री सहायता प्रदान करता है। मॉडल में दो खंड शामिल हैं- ज़नवोल्ट विराट पार्टनरशिप और ज़नवोल्ट विशाल पार्टनरशिप। इस कदम का उद्देश्य 2 करोड़ भारतीयों को बिजली देना है, जिनके पास निर्बाध बिजली नहीं है। लॉन्च के पहले दिन ही पूरे भारत में पचास से अधिक पार्टनर्स शामिल हुए। कंपनी की योजना इस साल के अंत तक इन पार्टनर्स की संख्या में 1000-1200 तक की बढ़ोतरी करने की है। वर्तमान में, ज़नवोल्ट बिज़नेस के लिए अपने पार्टनर्स को सिर्फ बैटरी सीरीज़ की पेशकश कर रहा है। हालाँकि, यह आने वाले समय में अपने होम-इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को पार्टनर्स के लिए भी पेश करने की योजना बना रहा है।

ज़नवोल्ट देशवासियों की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए दो प्रकार की बैटरी- टॉल ट्यूबलर और शॉर्ट ट्यूबलर इन्वर्टर बैटरी प्रदान करता है। ज़नवोल्ट का चीफ ड्राइवर, लंबे समय तक और बार-बार बिजली कटौती की समस्या का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसका लोगों को सामना करना पड़ता है।

ज़नपल्स के फाउंडर तथा सीईओ, श्री प्राणेश चौधरी कहते हैं, 'पहले हम विशेष रूप से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ज़नवोल्ट के प्रोडक्ट्स की पेशकश कर रहे थे, लेकिन अब पूरे भारत में हमारे पार्टनर्स होने के कारण, हम देश में बड़ी संख्या में लोगों तक पहुँचने में सक्षम होंगे। हम अपने पार्टनर्स को हर बिज़नेस से संबंधित सहायता प्रदान करने के लिए भी प्रतिबद्ध हैं।'

ज़नवोल्ट बैटरी एक एडवांस्ड ट्यूबलर प्लेट टेक्नोलॉजी के साथ आती है, जो लंबी बिजली कटौती के लिए निर्बाध बिजली बैकअप सुनिश्चित करती है। यह डिस्चार्ज की एक डीप साइकल पर काम करता है, जो लंबी अवधि में निरंतर शक्ति प्रदान करता है और बैटरी को मजबूती से चलाता है। इसमें माइक्रोपोरस सेपरेटर और वेंट प्लग भी हैं, जो पानी के उपयोग को न्यूनतम बनाते हैं। लंबे और लगातार बिजली कटौती को संभालने के लिए निर्मित, बैटरी में पीएसओसी (पार्टिकल स्टेट ऑफ चार्ज टेक्नोलॉजी) है, जो इसे तेजी से रिचार्ज भी करता है। ज़नवोल्ट बैटरीज़ 36 महीने की वॉरंटी के साथ आती हैं और हेवी-ड्यूटी एप्लीकेशंस के लिए आदर्श हैं। उन्हें एक्सीलेंट ओवरचार्ज टॉलरेंस, लंबे समय तक लगातार बिजली कटौती के दौरान बेहतर प्रदर्शन और न्यूनतम रखरखाव की आवश्यकता होती है।

सेबी ने 'उपयुक्त मानदंड' में बदलाव किया, चांदी का ईटीएफ शुरू करने को दी मंजूरी

नयी दिल्ली। एजेंसी

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने 'योग्य एवं उपयुक्त व्यक्ति' तय करने के मानदंड में बदलाव करते हुए देश में चांदी के लिए एक्सचेंज ट्रेडेड कोष (ईटीएफ) को शुरू करने की मंजूरी दे दी। इसके अलावा सेबी निदेशक मंडल ने कुछ निश्चित रक्षोपाय के साथ चांदी का ईटीएफ शुरू करने के लिए म्यूचुअल फंड नियमों में संशोधन किया है। चांदी का ईटीएफ सोने के ईटीएफ के लिए मौजूदा नियामकीय व्यवस्था की तर्ज पर ही शुरू किया जा रहा है। उपयुक्त व्यक्ति के संदर्भ में सेबी ने कहा कि यह मानदंड सिद्धांत आधार या नियम आधारित होगा। सिद्धांत आधारित मानदंड में ईमानदारी, नैतिक व्यवहार, प्रतिष्ठा, निष्पक्षता और चरित्र को शामिल किया जाएगा। सेबी ने बयान में कहा कि नियम आधारित मानदंड किसी व्यक्ति के योग्य एवं उपयुक्त होने के दर्जे को उसकी अयोग्यता के आधार पर तय करेगा।

वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने मूडीज के समक्ष की सरकारी साख परिदृश्य बेहतर करने की वकालत

नयी दिल्ली। एजेंसी

वित्त मंत्रालय के अधिकारियों और रेटिंग एजेंसी मूडीज के प्रतिनिधियों ने आर्थिक वृद्धि की संभावनाओं पर चर्चा की। बैठक के दौरान भारतीय अधिकारियों ने मूडीज़ के समक्ष भारत का

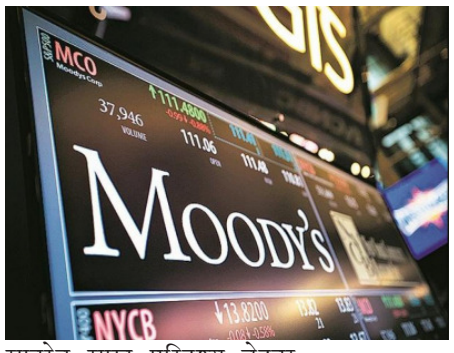

सावरेन साख परिदृश्य बेहतर करने की वकालत की। सूत्रों के अनुसार बैठक में मुख्य आर्थिक सलाहकार के वी सुब्रमणियम और आर्थिक मामलों के विभाग के अधिकारी तथा मूडीज के विश्लेषक शामिल हुए। यह बैठक मूडीज की सालाना सरकारी रेटिंग की कार्यवाही की तैयारी के हिस्से के रूप में हुई। मूडीज इनवेस्टर सर्विस ने पिछले साल भारत की सरकारी साख 'बीएए2' से कम कर 'बीएए3' कर दी थी। उसने कहा था कि निम्न वृद्धि दर की स्थिति लगातार बने रहने और बिगड़ती राजकोषीय स्थिति के जोखिमों को कम करने के लिए नीतियों के कार्यान्वयन में चुनौतियां होंगी। सरकारी साख पर परिदृश्य नकारात्मक है।

बैठक के दौरान वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने जून 2021 को समाप्त तिमाही में तीव्र जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) वृद्धि दर का जिक्र किया। साथ ही राजकोषीय घाटा और कर्ज के आंकड़े भी साझा किये। केंद्र का राजकोषीय घाटा अप्रैल -जुलाई, 2021 के दौरान वित्त वर्ष 2021-22 के लिये तय बजटीय अनुमान का 21.3 प्रतिशत रहा। इसका मुख्य कारण गैर-जरूरी खर्चों में कटौती और कर तथा गैर-कर राजस्व संग्रह में वृद्धि है। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में राजकोषीय घाटा सालाना लक्ष्य का 103 प्रतिशत तक पहुंच गया था। सरकार ने 2021-22 में 12.5 लाख करोड़ रुपये के सकल कर्ज का लक्ष्य रखा है। चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में आर्थिक वृद्धि दर 20.1 प्रतिशत रही। वहीं पिछले वित्त वर्ष 2020-21 जीडीपी वृद्धि दर में 7.3 प्रतिशत की गिरावट आयी थी।

सरकार जल्द नयी सहकारिता नीति की घोषणा करेगी

नयी दिल्ली। एजेंसी

केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा कि केंद्र जल्द ही एक नयी सहकारिता नीति लेकर आएगा और सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए राज्यों के साथ मिलकर काम करेगा। शाह केंद्रीय गृह मंत्री भी हैं। उन्होंने यह भी घोषणा की कि अगले पांच वर्ष में प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पीएसी) की संख्या बढ़ाकर तीन लाख की जाएगी। अभी पीएसी की संख्या लगभग 65,000 है। वह यहां पहले सहकारिता सम्मेलन या राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन में बोल रहे थे। सहकारिता मंत्रालय का गठन इसी साल जुलाई में किया गया था। विभिन्न सहकारी समितियों के 2,100 से अधिक प्रतिनिधियों और लगभग छह करोड़ ऑनलाइन प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि कुछ लोगों को आश्चर्य है कि केंद्र ने यह नया मंत्रालय क्यों बनाया क्योंकि सहकारिता राज्य का विषय है। शाह ने कहा कि इस पर कानूनी प्रतिक्रिया हो सकती है, लेकिन वह इस तर्क में नहीं पड़ना चाहते। उन्होंने जोर देकर कहा कि केंद्र राज्यों के साथ सहयोग करेगा और 'कोई टकराव नहीं होगा'। उन्होंने कहा, ''सहकारिता आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए हम सभी राज्यों के साथ मिलकर काम करेंगे।'' उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र को मजबूत और आधुनिक बनाने के लिए सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया है। प्रस्तावित नयी सहकारी नीति पर शाह ने कहा कि वर्ष 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा एक नीति लाई गई थी, और अब नरेंद्र मोदी सरकार एक नयी नीति पर काम शुरू करेगी। सहकारिता आंदोलन को पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक बताते हुए शाह ने कहा कि सहकारिता क्षेत्र देश के विकास में बहुत योगदान दे सकता है। उन्होंने कहा कि सहकारी समितियां भारत को 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। कराधान के मोर्चे और अन्य मुद्दों पर सहकारिता के सामने आने वाली समस्याओं का जिक्र करते हुए शाह ने कहा कि उन्हें इन चिंताओं की जानकारी है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सहकारिता क्षेत्र के साथ कोई अन्याय नहीं होगा।

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक सचिन बंसल द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13, प्रेस काम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 18, सेक्टर-डी-2, सांवेर रोड, इंडस्ट्रीयल एरिया, जिला इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक- सचिन बंसल

सूचना/चेतावनी- इंडियन प्लास्ट टाइम्स अखबार के पूरे या किसी भी भाग का उपयोग, पुनः प्रकाशन, या व्यावसायिक उपयोग बिना संपादक की अनुमति के करना वर्जित है। अखबार में छपे लेख या विज्ञापन का उद्देश्य सूचना और प्रस्तुतिकरण मात्र है। अखबार किसी भी प्रकार के लेख या विज्ञापन से किसी भी संस्थान की सिफारिश या समर्थन नहीं करता है। पाठक किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के लिए स्वविवेक से निर्णय करें। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र इंदौर, मप्र रहेगा।